प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई. बैठक में पीएम मोदी ने कहा, ''भारत एक युवा देश है. और यह अपने कार्यबल के कारण दुनिया भर में एक प्रमुख आकर्षण बन गया है.''

जनहितैषी

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:227 दिनांक:28-07-2024 रविवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने जीत के साथ आगाज किया है। ग्रुप-बी के एक मैच में न्यूजीलैंड को 2-1 से हराकर ओलंपिक का शानदार आगाज किया। भारत के लिए मनदीप सिंह और विवेक सागर प्रसाद ने गोल दागा।

विवादों में नीति आयोग की बैठक...नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इंडिया गठबंधन के सीएम नहीं हुए शामिल

वहीं सिर्फ 5 मिनट बोलने का मौका देने और बाद में माइक बंद करने का आरोप लगाते हुए बैठक से निकल गईं ममता

इंडिया ने किया बहिष्कार, ममता ने वॉकआउट

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। बैठक का इंडिया गठबंधन ने जहां बहिष्कार किया, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग बीच में छोडक़र बाहर आ गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में पक्षपात किया गया। ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया। माइक बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले। यह गलत है। विपक्ष की ओर से, सिर्फ मैं यहां प्रतिनिधित्व कर रही हूं, और इस बैठक में इसलिए भाग ले रही हूं क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत करने में मेरी अधिक रुचि है। नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं, यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय ताकत दें या योजना आयोग को वापस लाएं। मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और मैं बाहर आ गई।

इधर, सरकार ने ममता के इन आरोपों को झूठा बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता झूठ बोल रहीं, माइक बंद नहीं किया गया। हर मुख्यमंत्री के बोलने का समय तय था। नियमों के आधार पर उनके बोलने की बारी लंच के बाद आनी थी। लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें बैठक में सातवें वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था।

मेरा अपमान किया गया

ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कहा योजना आयोग को वापस ले आइए, मैंने कहा बंगाल को फंड दीजिए और आप भेदभाव मत कीजिए। मैंने बोला जब केंद्र सरकार चलाते हैं तो सारे राज्यों का सोचना चाहिए। मैं सेंट्रल फंड के बारे में बता रहा थी कि इसे पश्चिम बंगाल को नहीं दिया जा रहा है, तभी उन्होंने मेरा माइक म्यूट कर दिया। मैंने कहा कि विपक्ष से मैं ही बैठक में भाग ले रही हूं, आपको खुश होना चाहिए, इसके बजाय आप अपनी पार्टी और सरकार को अधिक वरीयता दे रहे। यह न केवल बंगाल का अपमान है, बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है। ये तो मेरा भी अपमान है। ममता बनर्जी ने बैठक से एक दिन पहले कहा था कि नीति आयोग खत्म करके, योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। उन्होंने आगे कहा- ये सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए। इस दौरे में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए किसी नेता से मेरी मुलाकात नहीं हो रही।

केंद्रीय मंत्रियों ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पार्लियामेंट में कोई कहता है मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, कोई कहता है मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ये कहीं ना कहीं अफवाह है और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उस मीटिंग में था नहीं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं वह पूरी तरह से मिसलीडिंग है। उन्होंने खुद कहा कि वह जल्दी निकलना चाहती हैं इसलिए उन्हें पहले बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें पूरा समय दिया गया। उनकी घंटी भी नहीं बजी थी। उन्होंने अपनी बात कही। फिर वह बाहर आ गईं और वही किया जो उन्हें करना था। अफसोस की बात है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मैंने नहीं देखा कि (नीति आयोग) बैठक में क्या हुआ। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह तथाकथित इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है क्योंकि ममता ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। वे जनता के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं इसलिए हाय तौबा मचा रहे हैं।

इन राज्यों के सीएम नहीं हुए शामिल

नीति आयोग की बैठक 5 घंटे चली। बैठक में इंडिया ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। बता दें कि इंडिया ब्लॉक के कई मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। इस बीच, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) नेता पिनाराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और सभी तीन कांग्रेस मुख्यमंत्रियों- कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सहित कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों (सीएम) ने नीति आयोग की अहम बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार भी बैठक में नहीं पहुंचे है और इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है। राज्य के दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हुए। भाजपा शासित राज्यों के ज्यादातर सीएम इस बैठक में मौजूद रहे।

15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य बनाया गया

केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को नीति आयोग की नई टीम का ऐलान किया था। इसमें चार पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी आयोग के अध्यक्ष और इकोनॉमिस्ट सुमन के. बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट वीके सारस्वत, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वीके पॉल और मैक्रो-इकोनॉमिस्ट अरविंद विरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे।

कोकीन के साथ थाईलैंड की महिला गिरफ्तार

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्स ने कोकीन के साथ थाईलैंड की एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला ट्राली बैग के अंदर 43 करोड़ रुपए की कोकीन छिपाकर लाई और देश में तस्करी करने की कोशिश की। कस्टम डिपार्टमेंट के मुताबिक, आरोपी महिला को 23 जुलाई को बैंकॉक से आते समय रोका गया। एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान उसके ट्रॉली बैग से 3.12 किलोग्राम कोकीन मिला। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 43.13 करोड़ रुपए है।

सावधान...यूपी, राजस्थान, कोंकण-गोवा और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

अगले चार दिन यूपी, राजस्थान के लिए बहुत भारी

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात बन हुए हैं। कही बाढ़ और भूस्खलन के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है।

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 17 दिन के ब्रेक के बाद मानसून फिर से आगरा के रास्ते पहुंच गया है। यूपी में 30 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इधर,गुजरात के भी कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 2700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2200 लोग नवसारी और 500 लोग तापी जिले के हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से यमुनोत्री धाम के दोनों गर्मकुंडों में मलबा भर गया है। मंदिर का ऑफिस, रसोई टूट गई है, मंदिर तक जाने वाला पैदल पुल भी बह गया है। भारी मलबा और बोल्डर से यमुनोत्री मंदिर को भी नुकसान हुआ है। जानकीचट्टी-यमुनोत्री पैदल मार्ग पर राममंदिर के निकट रजिस्ट्रेशन केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों को भागकर जान बचानी पड़ी।

आगे कैसा रहेगा मौसम...

28 जुलाई को पूर्वी राजस्थान, कोंकण-गोवा और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश (12 सेमी से ज्यादा) की चेतावनी दी गई है।

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और इंटीरियर कर्नाटक में भारी बारिश (7 सेमी तक) का अलर्ट है।

मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में अगले चार-पांच दिन लगातार बारिश का दौर रहेगा। राजस्थान में अब तक 185.3 एमएम औसत बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 1 फीसदी कम है।

पंजाब में फर्जी बिलों के जरिए घोटाला करने वाली कंपनियों पर टैक्स डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा

नई दिल्ली (ईएमएस)। पंजाब के कर विभाग के प्रवर्तन विंग की जांच में हजारों करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सोने का कारोबार करने वाली दो फर्मों के 860 करोड़ रुपए के जाली बिल तैयार करने और लोहे का कारोबार करने वाली 303 फर्मों के 4044 करोड़ रुपए के जाली बिल बनाने का खुलासा हुआ है। इसके अलावा, 68 फर्मों ने अपनी फर्मों को दूसरों के नाम पर पंजीकृत कर 533 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग का धंधा किया।

दिल्ली स्थित पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इन मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमृतसर में सोने का कारोबार करने वाली एक फर्म की जांच करने पर प्रवर्तन विंग ने पाया कि उक्त फर्म ने सोने की बिक्री और खरीद के लिए 336 करोड़ रुपए के जाली बिल बनाए थे। उन्होंने कहा कि जिन दो फर्मों से उक्त फर्म ने सोना खरीदा था, उनका पंजीकरण रद्द हो चुका था और इन फर्मों ने आगे सोने की कोई खरीद नहीं की थी।

पिथौरागढ़ में भारी बारिश का कहर, भागीरथी खतरे के निशान से ऊपर

पिथौरागढ़ (ईएमएस)। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब है। भारी बारिश के अलर्ट के बीच देहरादून, पिथौरागढ़ व बागेश्वर में स्कूल बंद किए गए हैं। वहीं चमौली जिले में दो वाहन पहाड़ी से गिरे मलबे में दब गए हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में शनिवार को तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं कई दौर की तेज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।उत्तरकाशी में गंगोत्री में भागीरथी का जलस्तर फिर बढ़ गया है। गंगोत्री में भागीरथी नदी का उफान घाटों के ऊपर तक पहुंच रहा है। गंगोत्री में आरती स्थल भागीरथ शिला से तक भागीरथी का जलस्तर पहुंच रहा है। तीर्थ पुरोहितों दान पत्र और अन्य सामान हटा दिया है। राज्य की सभी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पिथौरागढ़ में रामगंगा और काली नदी उफान पर चल रही है। वहीं पिथौरागढ़ में भारी बारिश से कई सड़कों पर मलबा आ गया है, जिसे रोड बंद हो गए।

भारी बारिश से थल मुनस्यारी मोटर मार्ग, धारचूला तवाघाट मोटर मार्ग, गंगोलीहाट बेरीनाग मोटर मार्ग, राईआगर सेराघाट अल्मोड़ा मोटर मार्ग बंद हो गया है। वहीं गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। भागीरथी नदी का पानी गंगोत्री धाम में घाट में ऊपर तक आ गया है। जिसके बाद यहां पुलिस प्रशासन ने लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है।

कनाडा के एडमोंटन में 6 पंजाबी गिरफ्तार

अमृतसर (ईएमएस)। कनाडा में एडमोंटन पुलिस ने दक्षिण एशियाई समुदाय को निशाना बनाकर जबरन वसूली करने के मामले में छह पंजाबी युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 34 वर्षीय मनिंदर सिंह धालीवाल के खिलाफ वारंट भी जारी किया है। पुलिस का मानना है कि मनिंदर धालीवाल जबरन वसूली करने वाले आपराधिक संगठन का सरगना है। इस संबंध में अब तक 40 घटनाओं की पहचान की जा चुकी है, जिसमें शुक्रवार की सुबह दक्षिण-पश्चिम एडमोंटन के कैवनाघ में एक अपार्टमेंट में आगजनी भी शामिल है।

संसद में बताया.....5 साल में विदेशों में करीब 633 भारतीय छात्रों की मौत

सबसे ज्यादा मौंते 172 कनाडा में हुई

नई दिल्ली (ईएमएस)। विदेशों में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, पिछले पांच सालों में 41 देशों में करीब 633 भारतीय छात्रों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 172 मौतें कनाडा में हुई हैं। इसकी जानकारी सांसद कोडिकुन्निल सुरेश के एक सवाल पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दी।

विदेश मंत्री ने बताया कि कनाडा में सबसे ज्यादा 172 भारतीय छात्रों की मौत हुई है। उसके बाद अमेरिका में 108 छात्रों ने दम तोड़ा। ब्रिटेन में 58, ऑस्ट्रेलिया में 57, रूस में 37 और जर्मनी में 24 छात्रों की मौत हुई है। हालांकि, विदेशों में भारतीय छात्रों पर हिंसक हमलों के बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारतीय मिशन/पोस्ट के पास मौजूद आंकड़ों से हाल में विदेश गए भारतीय छात्रों के खिलाफ हिंसा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

हिंसक हमलों में 19 छात्रों ने गंवाई जान

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विदेशों में हिंसक हमलों में 19 छात्रों ने जान गंवाई है। कनाडा में सबसे ज्यादा 9 छात्रों की मौत हुई है। उसके बाद अमेरिका में 6 और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन और किर्गिस्तान में एक-एक छात्र की जान गई है।

हाल ही में, दुनिया भर के देशों से फंसे भारतीय छात्रों को वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन) और ऑपरेशन अजय (इजराइल) के माध्यम से भारत लाया गया था।

विदेश में अभी इतने भारतीय छात्रा कर रहे पढ़ाई

विदेशों में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले भारतीय छात्रों की कुल संख्या 2024 में 1.33 मिलियन है। पिछले तीन वर्षों में विदेशों में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2022 में यह संख्या 0.75 मिलियन थी जो 2023 में बढ़कर 0.93 मिलियन हो गई और अब 1.33 मिलियन है। इस साल 1 जनवरी तक 101 देशों में हायर एजुकेशन हासिल कर रहे 13.35 लाख भारतीय छात्रों के बारे में एमईए की ओर से आंकड़ा पेश किया गया।

जालौन में कानपुर से अहमदाबाद जा रही यात्रियों से भरी स्लीपर बस हुई हाईजैक, पुलिस ने यात्रियों को बचाया

जालौन (ईएमएस)। उत्तरप्रदेश के जालौन में कानपुर से अहमदाबाद जा रही यात्रियों से भरी स्लीपर बस को बदमाशों ने शुक्रवार रात हाईजैक कर लिया। स्लीपर बस को हाईजैक करके भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। ड्राइवर और स्लीपर बस संचालक से बहस होने से नशे में धुत बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस की सतर्कता से तीन दर्जन से अधिक यात्रियों की जान बच गई।

हाईजैक बस में लगभग 36 लोग सवार थे। बदमाशों ने जालौन में इस बस को हाईजैक किया। बदमाश तीन दर्जन से अधिक यात्रियों से भरी स्लीपर बस लेकर भाग रहे थे। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मां वैष्णो ट्रेवल्स की स्लीपर बस रात के वक्त कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी। हाईजैक की घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल की है।

मौर्य और पाठक को सख्त निर्देश......योगी को झमादान

नई दिल्ली (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश की सियासत पर एक खबर छान कर सामने आ रही है। यूपी में किसी भी तरह का कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। इससे साफ हैं कि योगी के हाथ में ही होगी कमान। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। यूपी में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश हैं कि योगी अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाए। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही अपनी बात रखे। लगातार यूपी के कई नेताओं की ओर से बयानबाजी की जा रही थी।

खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया है। दोनों डिप्टी सीएम मौर्य और पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। मौर्य की कार्यसमिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कहीं उससे आलाकमान नाखुश है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई के मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी एक घंटे की मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सूलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है।

बजट के बाद.....7269 रुपये तक गिरे सोने के दम

नई दिल्ली (ईएमएस)। बजट के बाद से ही दिल्ली-एनसीआर सहित देश के सभी बड़े शहरों में सोने के रेट में गिरावट देखी जा सकती है। मोदी सरकार ने बजट में गोल्ड के इम्पोर्ट पर कस्टम डयूटी घटाने के ऐलान किया था। इसके बाद 6 दिन में गोल्ड के रेट में करीब 7269 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है।

हम आपको कुछ शहरों में 24 और 22 कैरेट गोल्ड का रेट बता रहे हैं। लेकिन रेट जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि 1 तोला सोना 10 ग्राम के बराबर होता है। दिल्ली में 22 कैरेट का 1 तोला सोना 64200 रुपये का है। यहां 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 67410 रुपये है। फरीदाबाद में आपको 22-24 कैरेट का गोल्ड दिल्ली वाले रेट पर ही मिलेगा। पटना में 22 कैरेट वाला गोल्ड 64900 रुपये का है। यहां 24 कैरेट का गोल्ड 68150 रुपये का मिल रहा है। कानपुर और लखनऊ में भी गोल्ड का रेट दिल्ली के बराबर ही है। इंदौर में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 64100 रुपये है। यहां 24 कैरेट गोल्ड का रेट 6731 रुपये है।

कैरेट किसी ज्वेलरी का वजन या सोने की शुद्धता को दर्शाने वाला यूनिट है। कैरेट से साफ होता है कि उस धातु में किसी और धातु का कितना मिश्रण है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड को सबसे शुद्ध माना जाता है। इसमें कोई और धातु मिश्रित नहीं होती है। हालांकि, प्योर गोल्ड बहुत जल्दी टूट जाता है,इसकारण इस थोड़ा मजबूत बनाने के लिए इसमें अन्य धातु जोड़ी जाती हैं। इसलिए अधिकांश गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट गोल्ड से बनाती हैं।

नीट के रिवाइज्ड रिजल्ट से टूटे सपने, 415 छात्र फेल करार

-नीट टापरों की संख्या 61 से घटकर 17 हुई

नई दिल्ली,(ईएमएस)। नीट मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के अदोशानुसार मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया। इस रिजल्ट के बाद 415 छात्र फेल करार दिए गए हैं। दरअसल ये छात्र नीट के मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर 162 से नीचे हो गए हैं। पहले यही छात्र पास हुए थे लेकिन रिवाइज्ड रिजल्ट में इन्हें फेल घोषित कर दिया गया है।

यहां बताते चलें कि प्रश्न संख्या 19 जो कि विवादित प्रश्न था उसके 5 अंक काटे गए हैं। इसके बाद इन छात्रों के अंक कम हुए और ये नीट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 162 अंकों से भी पीछे रह गए। प्रश्न 19 के सही उत्तर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करीब 4.20 लाख छात्रों के 5-5 अंक घटाए गए हैं। इससे नीट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो 1316268 थी से घटकर 1315853 हो गई। यहां यह भी बतलाते चलें कि रिवाइज्ड रिजल्ट के कारण मिनिमम क्वालिफाइंग कटऑफ जो पहले 164 अंक थी वह भी घटकर 162 हुई है। इसी प्रकार ओबीसी एससी और एसटी श्रेणियों के लिए पहले 163-129 थी जो कि रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद 161-127 हो गई है। इसी के साथ बड़ी खबर यह है कि नीट टॉपरों की जो संख्या पहले 61 थी वह घटकर 17 हो गई है। दरअसल रिवाइज्ड रिजल्ट में 44 टॉपरों के अंक 720 से घटकर 715 हो गए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा कराए जाने वाली याचिका को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया था।

नीट के रिवाज्ड रिजल्ट के अनुसार नीट रैंक वन (टापरों) में मृदुल मान्य आनंद, दिल्ली। आयुष नौगरैया, उत्तर प्रदेश। माजिन मंसूर, बिहार। प्रचिता, राजस्थान। सौरव, राजस्थान। दिव्यांश, दिल्ली। गुनमय गर्ग, पंजाब। अर्घ्यदीप दत्ता, पश्चिम बंगाल। शुभान सेनगुप्ता महाराष्ट्र। आर्यन यादव उत्तर प्रदेश। पलांशा अग्रवाल, महाराष्ट्र। रजनीश पी, तमिलनाडु। श्रीनंद शर्मिल, केरल। माने नेहा कुलदीप, महाराष्ट्र। तैजस सिंह, चंडीगढ़। देवेश जोशी, राजस्थान और इरम क़ाज़ी, राजस्थान के नाम हैं।

अमेरिका के व्योमिंग में प्लेन क्रैश....कई लोगों की मौत

हादसे के बाद जंगल में लगी आग

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका के व्योमिंग प्रांत में एक दूरदराजे के इलाके में प्लेन के क्रैश होने से कई लोगों की मौत हुई है। हादसे की वजह से जंगल में भी आग फैल गई है। बताया गया है कि पूर्वोत्तर व्योमिंग के दूर तक फैले जंगल के इलाके में ये विमान दुर्घटना हुई है। इसमें कई लोगों की मौतें हुईं और जंगल में भी आग लग गई।

ये विमान व्योमिंग के जिलेट शहर के उत्तरी हिस्से में दुर्घटना का शिकार हुआ है। कैम्पबेल काउंटी के अधिकारियों ने हादसे की जानकारी दी लेकिन मरने वालों की संख्या अभी तक जारी नहीं की गई है।

उन्होंने बताया कि दुर्घटनास्थल के पास हवा में धुआं उठता हुआ देखकर लोगों ने फोन पर स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विमान हादसे की वजह से जंगल में भारी आग भड़क गई। आग को विमान से पानी का छड़काव और दूसरी तरीकों का इस्तेमाल करके बुझाने की कोशिश हो रही है। माना जा रहा है कि विमान कई लोग सवार थे, विमान सवार सभी लोगों की मौत हो जाने का अंदेशा है। हाल ही में नेपाल में भी एक घातक विमान हादसा हुआ था। इस विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी।

अघोषित आय पर 60 फीसदी टैक्स चुका कर बचें जुर्माने और मुकदमेबाजी से

- नए नियमों का मकसद करदाताओं को अघोषित आय बताने के लिए प्रोत्साहित करना है

नई दिल्ली (ईएमएस)। अगर करदाता अपनी अघोषित आय पर 60 फीसदी कर चुकाने को तैयार हो जाता है तो उसे अलग से जुर्माना या ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। इन नियमों की घोषणा इसी मंगलवार को आए आम बजट में की गई है और ये 1 सितंबर से लागू होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा ?कि तलाशी के बाद कार्रवाई में आम तौर पर लंबा समय लगता है।

मगर प्रस्तावित योजना के तहत करदाता तलाशी के नतीजे मान लेता है और अपनी छिपाई गई आय पर 60 फीसदी कर चुकाता है तो मामला एक ही सुनवाई में खत्म हो सकता है। करदाता को कोई जुर्माना या ब्याज भी नहीं देना होगा। विशेषज्ञों ने कहा कि नए नियमों का मकसद करदाताओं को अघोषित आय बताने के लिए प्रोत्साहित करना है और इससे मुकदमेबाजी कम से कम 20 फीसदी घट सकती है।

इस योजना को ब्लॉक आकलन कहा गया है और यह तलाशी के नतीजे से 6 साल पहले तक की अघोषित कार्रवाई पर लागू होगी। सीबीडीटी प्रमुख ने कहा ?कि आम तौर पर आयकर विभाग द्वारा तलाशी के बाद आकलन अधिकारी अघोषित आय और साक्ष्यों की जांच करते हैं। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को कई नोटिस भेजे जाते हैं और सालों तक सुनवाई चलती है। इसमें काफी वक्त लग जाता है। अब अगर करदाता आयकर अधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार कर लेता है तो प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगर करदाता अधिकारी द्वारा तलाशी गई अघोषित आय पर कर चुका देता है तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन करदाता आकलन से ज्यादा अघोषित आय स्वीकार करता है तो अतिरिक्त रकम पर 50 फीसदी जुर्माना लगाया जा सकता है। अग्रवाल ने कहा कि तलाशी के प्रावधानों के कारण कई कार्यवाही होती हैं, अलग-अलग साल के लिए नोटिस भेजे जाते हैं। इतने अधिक नोटिसों के कारण विवाद या मुकदमा बहुत लंबा खिंच जाता है। मगर एक ही सुनवाई हो तो पूरे ब्लॉक या 6 साल की अवधि के मामले का निपटान हो सकता है। ब्लॉक अवधि से संबंधित कुल आय पर आयकर अधिनियम की धारा 113में बताई गई दर से कर वसूला जाएगा और पिछले वर्षों की आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

जब........कर्नाटक में कुत्ते का मांस का पार्सल मिलने पर हुआ नाटक

बेंगलुरु (ईएमएस)। कर्नाटक के सबसे व्यस्त ट्रेन स्टेशन के ओकालीपुरम प्रवेश द्वार पर अचानक हंगामा शुरु हो गया। ट्रेन में आए एक पार्सल को लेकर विवाद शुरू हुआ। पुलिस और आरपीएफ की टीमें ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली गई। तलाशी में पुलिस को बर्फ में जमा हुआ मांस मिला। आरोप है कि यह कुत्ते का मांस होटलों में सप्लाई होने जा रहा था। अधिकारी वर्तमान में शिपमेंट के स्रोत और क्या भेजने वाले के पास आवश्यक परमिट थे, इसकी जांच कर रहे हैं। खाद्य निरीक्षक भी स्थल पर पहुंचे और मांस को जब्त किया गया। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह मांस बाजार में 600 रुपये किलो में बेचा जा रहा था, जबकि मटन की कीमत 800 रुपये प्रति किलो है। हिंदू समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। कुत्ते का मांस बेचने के लिए राजस्थान से आया था।

पुलिस ने बताया कि उन्हें लंबे समय से बेंगलुरु में मटन के नाम पर कुत्ते का मांस बेचने की सूचना मिल रही थी। खास बात है कि बाजार से सस्ता बिकने के कारण, बड़े-बड़े होटलों में भी मटन के नाम पर कुत्ते का मांस परोसा जा रहा था। आरोप है कि मांस मैजेस्टिक के आसपास के होटलों में दूसरे मांस के साथ मिलाकर दिया जा रहा था। लोगों का आरोप है कि बेंगलुरु में बड़े लोगों के संरक्षण में मांस का कारोबार चल रहा है। जब राजस्थान से आए मांस के बक्सों को हटाया गया, तब उसमें खाल उतारे हुए कुत्तों के शव थे।

एक गौरक्षक के अनुसार, शहर में कुत्ते का मांस आयात किया जा रहा था। हालांकि, मांस का ऑर्डर देने वाले मांस व्यापारी अब्दुल रज्जाक ने आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि खेप का आदेश कानूनी रूप से दिया गया था और यह कुत्ते का मांस नहीं बल्कि भेड़ का मांस है। उन्होंने कहा कि हम व्यवसाय को कानूनी रूप से चला रहे हैं। जयपुर में हमारे बूचड़खाने हैं और ट्रेन से बेंगलुरु ले जाने से पहले मांस को-5 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करके लाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह कुत्ते का मांस नहीं है।

भारत में, कुत्ते के मांस का सेवन और व्यापार कानूनी बैन है। हालांकि विशिष्ट नियम राज्य के अनुसार भिन्न होते हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, पशुओं की हत्या और उपभोग को इस तरह से प्रतिबंधित करता है।

भ्रष्टाचार का सरगना कहे जाने पर भडक़े शरद पवार ने कहा -कोर्ट ने जिसे तड़ीपार किया, वो आज गृहमंत्री

मुंबई (ईएमएस)। एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनके बयान को लेकर पलटवार किया है। दरअसल अमित शाह ने बीते दिनों अपने एक बयान में शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया था। अब शरद पवार ने अमित शाह पर पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा कि ये हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से बाहर किया गया था, वो देश का इतना अहम मंत्रालय संभाल रहा है। उन्हें मैं याद दिला दूं कि आज जो आदमी देश का गृह मंत्री है, वह ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार (राज्य से बाहर) कर दिया था।

शरद पवार ने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे खिलाफ बयान दिया था और कुछ बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि शरद पवार देश के भ्रष्ट लोगों के कमांडर हैं। हैरानी है कि एक ऐसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री है, जिसे कानून के गलत इस्तेमाल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर कर दिया था! एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने कहा जिस व्यक्ति को निर्वासित किया गया था, वो आज देश का गृह मंत्री है। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वह देश को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अमित शाह को साल 2010 में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में दो साल के लिए राज्य से निर्वासित किया गया था। हालांकि बाद में साल 2014 में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया था।

अमित शाह ने पवार पर लगाए थे गंभीर आरोप

उल्लेखनीय है कि हाल ही में अमित शाह ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार पर तीखा हमला बोला था। अमित शाह ने शरद पवार को देश में भ्रष्ट लोगों का सरगना बताया था। अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, लेकिन देश की राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार हैं। अगर किसी राजनेता ने सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया तो वे शरद पवार थे और मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है। अब वे हम पर क्या आरोप लगाएंगे? अगर देश में भ्रष्टाचार को किसी ने संस्थागत बनाया है तो वो शरद पवार आप हैं और अब आप हम पर आरोप लगा रहे हैं?

जन हितैषी

सभी राज्यों से उभरे भाजपा नेताओं के बगावती स्वर

2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों से असंतोष और बगावत के स्वर सुनने को मिलने लगे हैं, लोकसभा के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। 2024 में भाजपा ने 370 पार का नारा लगाया था। लेकिन जब परिणाम आया, तो भारतीय जनता पार्टी 240 में सिमट कर रह गई। उसके बाद से ही देश के विभिन्न राज्यों से भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के विरोध में असंतोष और बगावत के स्वर उभरने लगे। किसी तरह से एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में बन गई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने अपने सभी विश्वस्त सहयोगियों को वही पद दिए जो उनके पास पूर्व में थे। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कामकाज को लेकर सभी राज्यों में भाजपा नेताओं के असंतोष और बगावती स्वर दिनों दिन मुखर होते जा रहे हैं। रही-सही कसर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानो से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती मिलने लगी है। भाजपा नेताओं के हौसले इतने बढ़ गए हैं, वह प्रधानमंत्री की नीति के खिलाफ ही खुलकर बोलने लगे है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी ने सबका-साथ सबका-विकास, नारे के स्थान पर खुद का नया नारा बुलंद कर दिया। जिसमें कहा गया जो हमारे-साथ, हम उसके-साथ, यह कहकर उन्होंने एक तरह से नरेंद्र मोदी का कद कम करने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में पसमांदा मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो हाथ बढ़ाया था। उसकी कोई सफलता प. बंगाल में नहीं मिलने से, मुसलमानों को लेकर जो रणनीति भाजपा ने बनाई थी। उसका भी बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेताओं के बीच असंतोष का स्वर बड़ा मुखर हो गया है। राज्य कार्य समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि अति आत्मविश्वास के कारण भाजपा का पतन हुआ है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने खुलेआम योगी के खिलाफ कार्य समिति और उसके बाद मोर्चा खोले हुए हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने भी केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज मुखर की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच खटपट की खबरें लगातार बाहर आ रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को भी पार्टी के अंदर से असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा विधायकों द्वारा उन्हें सीधी चुनौती दी जा रही है। भाजपा शासित राज्यों से भी संगठन में बैठे नेताओं द्वारा जिस तरह से असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। उससे ऐसा लगता है, 2012-13 में जो कांग्रेस की स्थिति थी। वही स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी में भी 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बनने लगी हैं। केंद्रीय बजट ने आग में घी डालने का काम किया है। केंद्र की सरकार को बचाए रखने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिए गए हैं। इसमें भाजपा शासित राज्यों की उपेक्षा किए जाने से डबल इंजिन की राज्यों में भाजपा के खिलाफ नाराजी का माहौल बन गया है। जिस तरह से सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में आपसी खटपट बढती चली जा रही है। उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है, 2013 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का भाजपा संगठन और सरकार में जो प्रभाव था। दोनों ही नेताओं को सभी राज्यों से चुनौती मिलना शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में भाजपा हर दिन कमजोर होती नजर आ रही है। इस स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी संगठन की चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ गई हैं। पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश का मामला जिस तरह से राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नुकसान हो रहा है।

भारतीय परिधान में दीक्षित हो रहे है आईआईटी रुड़की के छात्र!

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानि आईआईटी रुड़की में दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है।27 जुलाई को हो रहे आईआईटी रुड़की के 24वें दीक्षांत समारोह में नैसकॉम की अध्यक्ष देबजानी घोष मुख्य अतिथि होंगी,जिनकी मौजूदगी में छात्र छात्राएं भारतीय परिधान में उपाधि देंकर दीक्षित किए जा रहे है।जबाकि अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष डॉ. बीआर मोहन रेड्डी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे है। इस बार के दीक्षांत समारोह में 2513 छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की जा रही है। आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर केके पंत के शब्दों में, यह दीक्षांत समारोह आईआईटी के छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण का एक उत्सव है, इस बार के दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि देबजानी घोष है,जो नैसकॉम की अध्यक्ष हैं। वे प्रौद्योगिकी उद्योग क्षेत्र की एक अनुभवी व तीन दशक के इतिहास में शीर्ष पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हैं।सुश्री घोष ने जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति में दृढ़ता के साथ विश्वास किया हैं, और इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया हैं। वह उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे कि एआई, द्वारा प्रस्तुत अवसरों और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारत की विकास क्षमता को तेज करने में अपनी भूमिका को लेकर मुखर हैं। उनके नेतृत्व में, नैसकॉम ने समावेशी विकास और विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एआई के जिम्मेदार विकास और अपनाने में तेजी लाने की आवश्यकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है।इस समारोह की मुख्य अतिथि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) की अध्यक्ष देबजानी घोष जो कि प्रौद्योगिकी उद्योग की अनुभवी हैं और 30 वर्षों के इतिहास में नैसकॉम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। घोष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों की मुख्य समर्थक हैं।जिनका प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ा योगदान है।जिन 2513 छात्र-छात्राओं को उपाधि दी जा रही है, उनमें 1277 स्नातक छात्र, 794 स्नातकोत्तर और 442 पीएचडी के छात्र शामिल है। इस संस्थान ने 1847 से देश को तकनीकी ,मानव संसाधन और देश को गौरव प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।सन 1847 में 'थामसन कालेज आफ सिविल इंजीनियरिंग' के रूप में स्थापित आईआईटी रुड़की ने, देश को आजादी मिलने के बाद सन 1948 में रुड़की विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त की थी।9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) में परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हरिद्वार से कानपुर तक निकलने वाली उत्तरी गंग नहर का निर्माण जब शुरू हुआ तो तब इंजीनियरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थामसन ने रुड़की इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की थी ताकि गंग नहर के निर्माण में इंजीनियरों और सर्वेक्षकों की आपूर्ति की जा सके। अपनी स्थापना से लेकर आज तक 176 वर्षों में इस संस्थान ने देश को तकनीकी मानव संसाधन और राष्ट्रीय गौरव देने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की देश के आइआइटी संस्थानों में पांचवें स्थान पर आता है। वहीं यह संस्थान 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024' में 369वें स्थान पर है।यह संस्थान सन 1847 में 'थामसन कालेज आफ सिविल इंजीनियरिंग' के तौर पर स्थापित हुआ था। देश को आजादी मिलने के बाद इस कालेज को 1948 में रुड़की विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था।9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2001 में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) में तब्दील कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हरिद्वार से कानपुर तक निकलने वाली उत्तरी गंग नहर का निर्माण जब शुरू हुआ तो तब लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थामसन ने कालेज की स्थापना की थी ताकि गंग नहर के निर्माण में इंजीनियरों और सर्वेक्षकों की मदद की जा सके। अपनी स्थापना से लेकर आज तक 175 वर्षों में इस संस्थान ने देश को तकनीकी मानव संसाधन और जानकारी देने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की देश के आइआइटी संस्थानों में पांचवें स्थान पर आता है। वहीं यह संस्थान 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024' में 369वें स्थान पर है।24 से अधिक संकायों का संचालन कर रहे इस संस्थान की जब स्थापना की गई थी तब इसमें केवल सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े गिने-चुने संकाय ही थे और आज यह संस्थान 24 से ज्यादा संकायों का संचालन कर रहा है। इनमें प्रमुख रूप से अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, जैव विज्ञान एवं जैव अभियांत्रिकी,डिजाइन विभाग,जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन,बी आर्क, नैनो प्रौद्योगिकी, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन,परिवहन प्रणालियां, विद्युत अभियंत्रण, इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, रासायनिक अभियांत्रिकी, रसायनिकी विभाग, कंप्यूटर साइंस एवं अभियांत्रिकी , भूकम्प अभियांत्रिकी, कागज प्रौद्योगिकी, पालिमर एवं प्रोसेस अभियांत्रिकी भौतिकी विभाग, जल विज्ञान विभाग, जल एवं नवीकरणीय ऊर्जा,प्रबंधन विभाग, गणित विभाग,यान्त्रिकी एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी आदि शामिल हैं।निदेशक प्रोफेसर केके पंत ने छात्रों से कहा कि संस्थान में छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा एवं गणित सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जा रहे हैं। एनआइआरएफ रैंकिंग-2023 में आइआइटी रुड़की को भारत में वास्तुकला एवं नियोजन के शीर्ष संस्थानों के रूप में स्थान मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के कार्यान्वयन में भी संस्थान सबसे आगे है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हरिद्वार से कानपुर तक निकलने वाली उत्तरी गंग नहर का निर्माण जब शुरू हुआ तो तब लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थामसन ने कालेज की स्थापना की थी ताकि गंग नहर के निर्माण में इंजीनियरों और सर्वेक्षकों की मदद की जा सके। अपनी स्थापना से लेकर आज तक 175 वर्षों में इस संस्थान ने देश को तकनीकी मानव संसाधन और जानकारी देने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की देश के आइआइटी संस्थानों में पांचवें स्थान पर आता है। वहीं यह संस्थान 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024' में 369वें स्थान पर है।आईआईटी रुड़की में हाल ही में एनईपी-2020 के अनुरूप अपने स्नातक पाठयक्रम को संशोधित किया है।

इसका उद्देश्य छात्रों की वैश्विक आकांक्षाओं के साथ तालमेल बनाए रखना है। साथ ही यह संस्थान अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के साथ भी आईआईटी एक परियोजना पर कार्य कर रहा है। उद्योगों की जो समस्या है उसका निराकरण कैसे किया जाए, उस पर कार्य चल रहा है। जल की बर्बादी को रोकने के लिए संस्थान व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है। अभियांत्रिकी को जनहित के कार्यों में प्रयोग करने का एक अद्भुत और अनोखा प्रयोग संस्थान में हो रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर पंत का कहना है कि हम अपने संस्थान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 369 वीं रैंकिंग से 250 वीं रैंकिंग पर लाने के लिए प्रयासरत हैं। (लेखक- डॉ श्रीगोपाल नारसन/ ईएमएस) (लेखक आध्यात्मिक चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार है)

सरकार की उपलब्धि:हाल से मंडप तक

तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगातार परेशान कर रहे विपक्ष को सरकार के बजट पर न सही लेकिन राष्ट्रपति भवन के दो पुराने सभागारों के नाम बदलने के लिए संसद में एक राय होकर बधाई देना चाहिए । राष्ट्रपति भवन का दरबार हाल अब गणतंत्र मंडप और अशोका हाल अब अशोक मंडप कहलायेगा। सरकार के इस फैसले से गणतंत्र भी खुश और चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी खुश हो गए होंगे,इसलिए विपक्ष को भी खुश होना चाहिए।

देश और दुनिया लगातार देख रही है कि विपक्ष देश की अठारहवीं संसद में सरकार को चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है। बेचारे संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजजू से लेकर लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला ही नहीं बल्कि राज्य सभा के सभापति माननीय जयदीप धनकड़ भी परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वे विपक्ष को कौन सी मुगलई घुट्टी 555 लेकर पिलायें जिससे विपक्ष खुश नजर आये और सवाल पूछना छोड़कर देश के सीतारामी बजट पर चर्चा करे। आखिर देश की जनता सांसदों को सवाल करने और बहस-मुबाहिसे के लिए ही तो भेजती है। सांसदों को मेजें थपथपाने के लिए तो नहीं चुना जाता।

हमारी सरकार के खाते में तमाम नाकामियों के बावजूद तमाम उपलब्धियां भी हैं। आप बढ़ती हुई बेरोजगारी, मंहगाई और भ्रष्टाचार के साथ राजनीति के समानांतर बजट में भी अदावत के इस्तेमाल को यदि सरकार की उपलब्धि नहीं मानते तो ये आपकी तंगदिली है। हमारी सरकार ने पिछले एक दशक में जो किया वो पिछली सरकारें साठ साल में नहीं कर पायीं। भले ही पिछली सरकारें कांग्रेस की हों या भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधनों की। सरकार ने देश का परिदृश्य बदला हो या न बदला हो लेकिन कानूनों ,शहरों,स्टेशनों ,सड़कों,संस्थानों ,पाठयक्रमों और इमारतों के ही नहीं बल्कि अब तो राष्ट्रपति भवन के कक्षों के नाम तक बदलकर दिखा दिए। ये कोई छोटी -मोटी उपलब्धि है ? सरकार लगातार देश को उसकी खोई हुई,छीनी हुई संस्कृति और वैभव वापस कर रही है।

देश की तकदीर बदलने में अरबों-खरबों मुद्रा की जरूरत पड़ती है । इसके लिए विदेशों से ,विदेशी बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। इस वजह से विकास पर कम ब्याज पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन नाम बदलने पर फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं होती और काम हो जाता है। अलाहबाद प्रयाग हो जाता है ,फैजाबाद अयोध्या हो जाती है ,हबीबगंज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो जाता है ,मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो जाता है। आप का पता नहीं लेकिन मै तो अपनी सरकार की इन उपलब्धियों पर लट्टू हूँ।

मुझे भी सरकार की तरह विपक्ष की बालक बुद्धि पर तरस आता है कि वो कहाँ नीट और किसानों के मुद्दे पर बहस करने की मांग करती है। उसे किसानों से क्या लेना ? नीट से क्या लेना ? अरे जब देश की सबसे बड़ी अदालतें तक नीट के मामले में सरकार के साथ हैं,किसानों को दिल्ली में प्रवेश न करने देने के मामले में सरकार के साथ हैं ,तो विपक्ष को साथ देने में क्या ऐतराज है ? देश ये राज जानना चाहता है। क्या सरकार को परेशान करने के पीछे कोई विदेशी हाथ तो नहीं ? क्योंकि जिन देशी हाथों को सरकार के लिए परेशानी खड़ी करना चाहिए थी वे तो बैशाखी बनकर उसकी मदद कर रहे हैं। साम्प्रदायिकता के मुखर विरोधी जेडीयू और टीडीपी की भूमिका बदली हुई है।

देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दस मोदी के नेतृत्व में भाजपा,जेडीयू और टीडीपी की सरकार बने कोई दो महीना होने को है। इन दो महीने में प्रधानमंत्री जी कम से कम तीन विदेश यात्राएं कर आये। उनकी सरकार ने देश के लिए सातवीं मर्तबा सीतारामी बजट संसद में पेश कर दिया। प्रधान जी ने अपनी मातृ संस्था आरएसएस के कहने के बावजूद मणिपुर को लेकर अपना नजरिया नहीं बदला । अहंकार नहीं त्यागा। बदले में संघ की इमदाद के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने पर लगी 58 साल पुरानी रोक जरूर लगा दी अब आप ही बताइये की 48 दिन पुरानी सरकार देश के लिए ,देश की जनता के लिए और क्या कर सकती है ? जो काम आपातकाल के बाद बनी सरकार नहीं कर पायी ,महामना अटल बिहारी बाजपेयी तीन बार प्रधानमंत्री बनकर नहीं कर पाए ,वो काम माननीय मोदी जी ने करके दिखा दिया।

देश के अड़ियल विपक्ष को देश की जनता देख रही हो या न देख रही हो किन्तु ऊपर वाला जरूर देख रहा है । एक धर्मभीरु सरकार को इस तरह परेशान करना बिलकुल अच्छी बात नहीं है । सरकार ने अपने नए बजट में जनता के लिए ही नहीं ऊपर वालों के लिए भी पर्याप्त बजट प्रावधान किये है। देश में स्कूलों ,अस्पतालों ,सड़कों ,पुलों की कमी भले बनी रहे किन्तु तीन नए धार्मिक कॉरिडोर जरूर बनाये जाने के लिए बजट प्रावधान किया गया है। सरकार इस बार अयोध्या हारी ,बद्रीनाथ हारी लेकिन उसने भगवान के बजट में कोई कटौती नहीं की । विपक्ष को भी ऐसी ही दरियादिली का मुजाहिरा करना चाहिए। विपक्ष को कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि सास को भी काम करने के लिए सौ ड100 . दिन दिए जाते हैं ,फिर सरकार के तो अभी 48 दिन ही हुए हैं। विपक्ष चाहे तो सौ दिन बाद तीन राज्यों की तीन विधानसभाओं के समय सरकार से दो-दो हाथ कर ले । अभी तो बजट पर बहस करे।

आखिर विपक्ष देश की सियासत में नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करना चाहता है। जनता को तो विपक्ष के प्यार बांटते चलो अभियान से राहत मिल चुकी है। अब बारी सरकार की है। विपक्ष अब संसद में तकरार से नहीं बल्कि मोहब्बत से काम ले। मुमकिन है कि सरकार भी थोड़ी रहमदिली दिखाए ,अन्यथा देश की संसद को थोक में सांसदों के निलंबन का तजुर्बा है ही। (लेखक - राकेश अचल / ईएमएस)

नये कानून से बुजुर्ग मां-पिता की सुध लेने की सार्थक

देश में वृद्धों के साथ उपेक्षा, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना बढ़ती जा रही है, बच्चे अपने माता-पिता के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते, वे उनके जीवन-निर्वाह की जिम्मेदारी भी नहीं उठाना चाहते हैं, जिससे भारत की बुजुर्ग पीढ़ी का जीवन नरकमय बना हुआ है, वृद्धजनों की पल-पल की घुटन, तनाव, जीवन-निर्वाह करने की जटिलता एवं उपेक्षा को लेकर समय-समय पर जहां न्यायालयों ने अपनी चिन्ता जतायी है, वहीं सरकार ने कानून बनाकर बुजुर्गों को उन्नत एवं शांति देने के प्रयास किये हैं, लेकिन इसके बावजूद वृद्ध लोगों का जीवन कष्टमय एवं जटिल बना हुआ है। वृद्ध माता-पिता की देखभाल एवं भरण-पोषण की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अदालतों में गुजारा-भत्ते से जुड़े विवाद बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिये बाध्य करने वाले 2007 के कानून में बदलाव लाकर, इसका दायरा बढ़ाने के मकसद से नये कानून लाने की तैयारी में है। माता-पिता और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े वर्षों पुराने कानून को प्रभावी व व्यावहारिक बनाने की कोशिश निश्चित रूप से सामाजिक एवं पारिवारिक ताने-बाने में वृद्धों को सम्मानजनक जीवन देने की सार्थक एवं सराहनीय कोशिश है।

इस समय देश में करीब 10.5 करोड़ बुजुर्ग लोग हैं और 2050 तक इनकी संख्या 32.4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। भारत सहित 64 ऐसे देश होंगे जहाँ 30 प्रतिशत आबादी 60 वर्ष से अधिक उम्र की होगी। एकल परिवार के दौर में बुजर्गों की देखभाल और भरण पोषण एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रही है ऐसे में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुजुर्गों की देखभाल के लिये मेंटिनेंस ऐंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स ऐंड सीनियर सिटिजन ऐक्ट 2007 में संशोधन की पहल की है, नये बिल के मुताबिक अब घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी सिर्फ बेटे ही नहीं, बल्कि बहू-दामाद, गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बेटे और बेटियों की भी होगी। बिल लाने का मकसद बुजुर्गों का सम्मान सुनिश्चित करना है। पहले वृद्ध माता-पिता अपनी संतानों से दस हजार रुपये तक का गुजारा भत्ता पाने के हकदार थे। बताया जा रहा है कि नये विधेयक के अनुसार अब माता-पिता का गुजारा भत्ता बच्चों की आर्थिक हैसियत से तय होगा। वहीं बच्चों के साथ कटुता कम करने के प्रयासों में माता-पिता व बुजुर्गों को त्यागने अथवा दुर्व्यवहार पर बच्चों को दी जाने वाली सजा में कमी करने की भी तैयारी है। ऐसा सामाजिक संगठनों से विमर्श के बाद किया गया है। क्योंकि लंबी सजा से माता-पिता और बच्चों के संबंधों में ज्यादा खटास बढ़ती है। कहा जा रहा है कि सरकार बजट सत्र में इस विधेयक को पेश कर सकती है। दरअसल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े 2007 के कानून में बदलाव की पहल तब की, जब समाज में बुजुर्गों की अनदेखी व दुर्व्यवहार के मामले तेजी से बढ़े हैं।

भारतीय संस्कृति एवं सभी धार्मिक ग्रंथों में माता पिता को भगवान का रूप माना गया है और उनकी निःस्वार्थ सेवा करने की बात कही गयी है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करना तो दूर उल्टा उन्हें परेशान करते रहते हैं। इसलिये विभिन्न राज्यों की सरकारें बुजुर्ग आत्म-सम्मान के लिये नये कानून बना रही है। उत्तरप्रदेश में योगी सरकार अब बुजुर्ग मां-बाप की संपत्ति हड़प कर उन्हें बेदखल करने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत माता-पिता की संपत्ति हड़प कर उन्हें घर से बाहर निकलने वाले बेटे-बेटियों की खैर नहीं होगी। कुछ दूसरी तरह से असम सरकार ने वृद्धों की उपेक्षा पर विराम लगाने की दृष्टि से ही राज्य कर्मचारियों के लिए नवंबर में दो विशेष अवकाश शुरू किए हैं, ताकि वे अपने माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिता सकें। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी घोषणा में परिवार के महत्व पर जोर दिया। 6 और 8 नवंबर को मिलने वाली ये विशेष छुट्टियां कर्मचारियों को उनके बुजुर्ग माता-पिता या सास-ससुर से जुड़ने के लिए हैं। इसका उद्देश्य परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति सम्मान और देखभाल दिखाना है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी घोषणा में परिवार के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि 'माता-पिता का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। एक आदर्श नागरिक के रूप में, अपने माता-पिता की भलाई सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।'

असम सरकार ने पूर्व में राज्य विधानसभा ने असम कर्मचारी माता-पिता जिम्मेदारी एवं जवाबेदही तथा निगरानी नियम विधेयक, 2017 या प्रणाम विधेयक भी पारित कर चुकी है। इसका मकसद यह सुनिश्चत करना है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपने वृद्ध हो रहे माता-पिता या शारीरिक रूप से अशक्त भाई-बहन की देखभाल करें नहीं तो उनके वेतन से पैसे काट लिए जाएंगे। पूरे देशभर के लोग इस कानून को असम सरकार का एक अच्छा कदम बताया। नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति (सरकारी कर्मचारी) उसपर निर्भर माता-पिता की देखभाल नहीं करता तो उसके कुल वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाएगा और वह राशि माता-पिता के खाते में डाल दी जाएगी। दिव्यांग (शारीरिक रूप से अशक्त) भाई-बहन होने की स्थिति में वेतन से 15 प्रतिशत तक हिस्सा काट लिया जाएगा।

अब केन्द्र सरकार द्वारा 2007 के कानून में बदलाव लाकर, नये विधेयक में इससे जुड़े कानून की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, मंत्रालय ने कानून में बदलाव की पहल वर्ष 2019 में कर दी थी। इसी साल लोकसभा में एक विधेयक भी पेश किया गया था। इसके व्यापक पहलुओं की पड़ताल के लिये विधेयक को बाद में संसदीय समिति के पास भेज गया था। संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक बार फिर एक विधेयक को संसद में पेश किया था। लेकिन वह पारित नहीं हो पाया था। कालांतर 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के कारण विधेयक निष्प्रभावी हो गया था। जिसके बाद अब सरकार नये सिरे से इस विधेयक को संसद में लाने की तैयारी में है। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक में कई नये प्रावधानों को जोड़ा गया है। विधेयक में प्रत्येक जिले में बुजुर्गों की गणना, मेडिकल सुविधाओं से लैस वृद्ध आश्रम व जिला स्तर पर एक सेल गठित करने जैसे प्रावधान हैं।

संतान द्वारा बुजुर्गों की आवश्यकताओं को पूरा न करना गरिमा के साथ स्वतंत्र जीवन जीने जैसे मानवाधिकारों का हनन है। संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने इस स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया है। वृद्धों की उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार के इस गलत प्रवाह को रोकने की दृष्टि से नया कानून प्रभावी कदम है, इससे बच्चों की अपने माता-पिता की उपेक्षा पर विराम लग सकेगा। सभी के लिये बुजुर्ग पीढ़ी के लिए सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी ही चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ हर बुजुर्ग अपने बुढ़ापे को गरिमा, आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वस्थता के साथ जी सके। वृद्धों को बंधन नहीं, आत्म-गौरव के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा है। वृद्धों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं, वह अचानक ही नहीं हुई, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अधुनातन बोध के तहत बदलते सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े-बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। यदि परिवार के वृद्ध कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रुग्णावस्था में बिस्तर पर पड़े कराह रहे हैं, भरण-पोषण को तरस रहे हैं तो यह हमारे लिए वास्तव में लज्जा एवं शर्म का विषय है। वर्तमान युग की बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि वृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा-सहमा खड़ा है, वृद्धों की उपेक्षा स्वस्थ एवं सुसंस्कृत परिवार परम्परा पर काला दाग है, यह आदर्श-शासन व्यवस्था के लिये भी शर्म का विषय है। इन त्रासद एवं डरावनी स्थितियों से वृद्धों को मुक्ति दिलाने के लिये नये कानून बनाने के साथ उसे सख्ती से लागू करने की भी अपेक्षा है। (लेखक- ललित गर्ग / ईएमएस)

शब्द पहेली - 8081

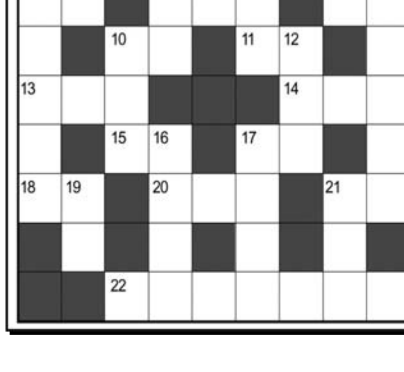

बाएँ से दाएँ

1. भगवान, ईश्वर, रब-7
6. रुपये का सोलहवां भाग-2
7. मध्यप्रदेश का एक भाग-3
8. मूल्य, कीमत, दर-2
10. जी, इच्छा, चित-2
11. नलका, टोंटी-2
13. बारीक, सूक्ष्म-3
14. रेखा, लाइन-3
15. रग, नाड़ी-2
17. अधिकार -2
18. वध, कत्ल, मर्डर-2
20. दौड़ने वाला, धावक (अंग्रेजी-3)
21. एक आंख वाला-2
22. निंदा करना, प्रतिष्ठा खंडित करना-4,3

ऊपर से नीचे

2. निर्माण, बनाना-3
3. एक संगीतकार-4
4. गाड़ी चलानेवाला-4
5. नखरा-2
6. आरामदेय-5
9. इच्छा पूरी करना-2,3
10. चिंतन-3
12. उत्साह, जिज्ञासा-3
16. हद, सीमा, बार्डर-4
17. हमेशा, सदैव-4
19. बलिदान, परित्याग, विरक्ति-2
21. नास्तिक (उर्दू-2)

शब्द पहेली-8080 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

ओलंपिक :आज गोल्ड पर निशाना लगाने उतरेगी मनू भाकर ,10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंची

नई दिल्ली (ईएमएस)। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत की स्टार निशानेबाज मनू भाकर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंच गई है। इसके पहले भारत के पुरुष खिलाड़ी इस इवेंट में क्वालीफायर से आगे बढ़ने में नाकाम रहे थे। मनू ने शानदार प्रदर्शन कर सटीक निशाना साधकर मेडल पर दावेदारी ठोक दी है। टॉप 8 में रहने वाले निशानेबाज को फाइनल राउंड में जगह मिलती है। कुल 580 अंकों के साथ मनू ने तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई।

निशानेबाज मनू ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहली तीन सीरीज के बाद दूसरे नंबर पर बनी हुई थी। वहीं भारत की एक और निशानेबाज रिदिमा सांगवान 24वें स्थान पर खिसक गई। चौथी सीरीज के बाद मनू तीसरे स्थान पर पहुंच गई। पहली तीन सीरीज में उन्होंने 97, 97, 98 स्कोर किया जबकि चौथी सीरीज में 96 का स्कोर कर सकी। रिदिमा ने अच्छी वापसी कर 24वें नंबर से उपर चढ़कर 16वें स्थान पर पहुंची।

इसके बाद उन्होंने आखिरी सीरीज में भी 96 स्कोर के साथ फाइनल में जगह बना ली। 10 मीटर एयर पिस्टल वूमेंस इवेंट वह तीसरे स्थान पर रही और अब मेडल की दावेदारी पेश करेंगी। रिदिमा सांगवान 15वें नंबर पर रहीं।

मनू भाकर से देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक में शनिवार को 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह बनाने के बाद उन्हें एक दिन का आराम मिलेगा। रविवार दोपहर 3.30 बजे मेडल हासिल करने के लिए मनू फाइनल में उतरेंगी।

पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड चीन की झोली में

पेरिस (ईएमएस)। 2024 पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल चीन की झोली में गया है। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट के गोल्ड मेडल मुकाबले में चीन ने साउथ कोरिया को 16-12 से हराया। हुआंग यूटिंग और शेंग लिहाओ ने यह गोल्ड मेडल जीता। यूटिंग 19 साल के हैं, वहीं शेंग सिर्फ 17 साल के है। यह जोड़ी इस इवेंट की वर्ल्ड चैंपियन भी है। साउथ कोरिया के केउम जिहयोन और हाजुन पार्क को सिल्वर से संतोष करना पड़ा।

ओलंपिक में यह हुआंग यूटिंग का दूसरा मेडल है। 16 साल की उम्र में उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया था। शेंग लिहाओ ने 17 साल की उम्र में अब करीब सभी इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। उनके नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीन गोल्ड हैं। इसके अलावा पिछले साल एशियन गेम्स में भी उन्होंने तीन गोल्ड मेडल जीते थे। क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप-2 पर रहने वाली जोड़ी के बीच खिताबी मुकाबला होता है। फाइनल में हर राउंड के विजेता को दो पॉइंट मिलते हैं। हर टीम का एक शूटर एक-एक बार शूट करता है। इसके बाद दोनों के पॉइंट को जोड़ दिया जाता है। ज्यादा पॉइंट हासिल करने वाली टीम को 2 अंक दे दिए जाते हैं। पहले 16 अंत पर पहुंचने वाली टीम विजेता होती है।

कजाकिस्तान की जोड़ी एलेक्जेंड्रा ले और इस्लाम सतपायेव ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में इस जोड़ी के सामने जर्मनी की चुनौती थी। एलेक्जेंड्रा ले और इस्लाम सतपायेव ने 630.8 अंक के साथ इस मैच के लिए क्वालिफाई किया था। ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला एकतरफा रहा। अन्ना जानसेन और मैक्सिमिलियन उलब्रिच की जर्मन जोड़ी 17-5 से हार गई। इस तरह 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट के सभी तीन मेडल एशियाई देश को खाते में आए।

पेरिस ओलंपिक : भारत के बलराज नौकायन हीट में चौथे स्थान पर, रेपेचेज में पहुंचे

चेटेरोक्स (ईएमएस)। शनिवार को पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारत के एकमात्र नौकायन (रोइंग) खिलाड़ी बलराज पंवार यहां पुरुष एकल स्कल स्पर्धा की पहली हीट में चौथे स्थान पर रहे और अब रेपेचेज में हिस्सा लेंगे। पच्चीस साल के बलराज ने सात मिनट 7.11 सेकेंड का समय लिया। वह न्यूजीलैंड के थॉमस मैकिनटोश (छह मिनट 55.92 सेकेंड), स्टीफानोस एनतोस्कोस (सात मिनट 1.79 सेकेंड) और अब्देलखालेक एलबाना (सात मिनट 5.06 सेकेंड) से पीछे रहे। प्रत्येक हीट से शीर्ष तीन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। रेपेचेज के जरिए बलराज को सेमीफाइनल या फाइनल में जगह बनाने का दूसरा मौका मिलेगा। बलराज चीन में 2022 एशियाई खेलों में चौथे स्थान पर रहे थे और कोरिया में एशियाई तथा ओसियाना ओलंपिक क्वालीफिकेशन रेगाटा में कांस्य पदक जीता था।

पहले दिन शूटिंग में भारत के हाथो निराशा लगी

चेटेरोक्स (ईएमएस)। खेलों के महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक में भारत से इस बार कम से कम 12 से 15 पदक की उम्मीद की जा रही है, पर पहले दिन के पहले मुकाबले में भारत को निराश होना पड़ा । दिन के पहले इवेंट में उतरी भारतीय निशानेबाजी टीम फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही. भारतीय निशानेबाज शनिवार को ओलंपिक खेलों के 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम क्वालीफिकेशन चरण में बाहर हो गए। भारत की दो जोड़ियां इस स्पर्धा में भाग ले रही थी। रमिता और अर्जुन बाबूता 628.7 के कुल स्कोर के साथ छठे, जबकि इलावेनिल वलारिवन और संदीप सिंह 626.3 के कुल स्कोर के साथ 12वें स्थान पर रहे।

रमिता और अर्जुन की जोड़ी ने एक समय कुछ उम्मीद बनाई थी, लेकिन यह भारतीय जोड़ी तीन शॉट शेष रहते पांचवें स्थान पर थी, और आखिर में पदक राउंड के कट ऑफ से 1.0 अंक पीछे रह गई। अर्जुन ने दूसरी सीरीज में शानदार शुरुआत की और 10.5, 10.6, 10.5, 10.9 का स्कोर बनाया। रमिता ने दूसरी सीरीज में 10.2, 10.7, 10.3, 10.1 का स्कोर बनाया। इससे यह जोड़ी शीर्षक आठ में तो पहुंच गई लेकिन पदक राउंड में जगह बनाने के लिए यह स्कोर पर्याप्त नहीं था। पदक राउंड में पहुंचने के लिए शीर्ष चार में जगह बनाना जरूरी था. चीन, कोरिया और कजाकिस्तान की टीम क्वालीफिकेशन दौर में पहले तीन स्थानों पर रही। चीन, कोरिया, जर्मनी और कजाकिस्तान 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम पदक मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। रैंकिंग में केवल शीर्ष चार टीमें ही पदक राउंड में आगे बढ़ेंगी, जिसमें पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमें स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।

टेस्ट सीरीज: वेस्टइंडीज 282 रन पर सिमटी, इंग्लैंड ने भी खोए 3 विकेट, गेंदबाज छाए

बर्मिंघम,(ईएमएस)। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा रहा। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर वेस्टइंडीज ने अच्छी शुरुआत की। 76 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा। यहां से मैच का पासा पलटा और इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 282 रनों पर ऑलआउट कर दिया। वेस्टइंडीज ने भी खेलने उतरी इंग्लैंड के टॉप तीन बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा दिया। अभी भी मेहमान टीम के पास 244 रनों की बढ़त है। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने अर्धशतक लगाकर वेस्टइंडीज को अच्छी शुरुआत दी थी। पहले विकेट के लिए उन्होंने मिक्ली लुइस के साथ 76 रन बनाए। लुइस 26 रन बनाकर गस एटनिंसन का शिकार हुए। इसके बाद किर्क मैकेंजी 12 और एलिक अथानजे दो रन बनाकर आउट हो गए। ब्रेथवेट (61) और कैवेम हॉग (13) के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर पांच विकेट पर 115 रन था। 39 रन बनाने में टीम ने पांच विकेट खो दिए।

यहां से जेसन होल्डर और विकेटकीपर जोशुआ डा सिल्वा ने पारी को संभालने का काम किया। दोनों ने शतकीय साझेदारी खेली। होल्डर ने 59 रनों की पारी खेली लेकिन सिल्वा एक रन से अर्धशतक बनाने से चूक गए। दोनों के बीच 109 रनों की साझेदारी हुई। निचले क्रम में अल्जारी जोसेफ ने 15 तो नंबर-11 शमार जोसेफ ने 16 रनों का योगदान दिया। वेस्टइंडीज पहली पारी में 282 रन बना सकी। एटकिंसन को चार, क्रिस वोक्स को तीन विकेट मिले।

कजाकिस्तान ने ने पहला कांस्य पदक जीता

चेटेरोक्स (ईएमएस)। कजाकिस्तान ने शनिवार को 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य अपने नाम किया। कजाकिस्तान ने पदक मैच में जर्मनी को 17-5 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक का पहला पदक जीता। कजाकिस्तान के निशानेबाज एलेक्जेंड्रा ले और इस्लाम सतपायेव ने मैच की शुरुआत में ही माहौल तैयार कर दिया और जर्मनी के 20.7 के मुकाबले 21.4 के स्कोर के साथ पहला राउंड जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली। जर्मनी की अन्ना जानसेन और मैक्सिमिलियन उलब्रिच के उत्साही प्रयास के बावजूद, जो स्कोर 3-3 और 4-4 से बराबर करने में सफल रहे, क़ज़ाख जोड़ी ने कभी भी मैच पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। ले और सतपायेव की निरंतरता जर्मनों के लिए बहुत अधिक साबित हुई। संक्षिप्त मुकाबले के बाद, कजाकिस्तान आगे बढ़ गया और अगले तीन राउंड जीतकर 10-4 की बढ़त हासिल कर ली। हालाँकि जर्मनी एक और राउंड बराबर करने में कामयाब रहा, लेकिन यह केवल एक अस्थायी राहत थी क्योंकि क़ज़ाकों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और अंतत: एक आरामदायक जीत हासिल की।

आज 8वीं बार चैंपियन बनने उतरेंगी हमारी छोरियां, महिला एशिया कप फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला

नई दिल्ली (ईएमएस)। जीत के रथ पर सवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को महिला एशिया कप फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेल रही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया है। जबकि मेजबान श्रीलंका ने पाकिस्तान को पटखनी दे फाइनल में जगह बनाई है। मौजूदा चैंपियन भारत की नजर रिकॉर्ड 8वीं बार चैंपियन बनने पर है। फाइनल 28 जुलाई को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा।

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने लीग चरण में पाकिस्तान को 7 विकेट से, संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से और नेपाल को 82 रन से हराया। सेमीफाइनल में टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया था। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अभी तक बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। जिसके बदौलत टीम अजेय होकर फाइनल तक पहुंची है।

सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अभी तक टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है। लेकिन टीम प्रबंधन गेंदबाजी विशेषकर दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह के प्रदर्शन से काफी खुश होगा। दीप्ति ने टूर्नामेंट में अभी तक सर्वाधिक 9 विकेट झटके हैं, जबकि रेणुका सात विकेट लेकर तालिका में तीसरे नंबर पर है। इन दोनों का इकोनॉमी रेट भी शानदार है, जिसका मतलब है कि उन्होंने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है।

इन दोनों की कसी गेंदबाजी का फायदा अन्य गेंदबाजों को भी मिला है। बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव इसका उदाहरण है जिन्होंने अभी तक 5.5 के इकोनॉमी रेट से 6 विकेट लिए हैं। भारतीय टीम के लिए कोई विभाग चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत और जेमिमा रोड्रिग्स को बल्लेबाजी के कम मौके मिलने से वह थोड़ा चिंतित हो सकता है। दूसरी ओर श्रीलंका भी अभी तक अजेय रहा है। मेजबान ने टूर्नामेंट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी हासिल की है। श्रीलंका ने ग्रुप चरण में मलेशिया को 144 रन से हराया था।

श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक 243 रन बनाए हैं, लेकिन उनके अलावा श्रीलंका की कोई भी अन्य बल्लेबाज 100 रन तक नहीं पहुंची है। भारत को जीतने के लिए श्रीलंकाई कप्तान को सस्ते में आउट करना होगा। भारत के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने श्रीलंका के गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा होगी। ऑफ स्पिनर कविशा दिलहारी (सात विकेट) को छोड़कर अन्य श्रीलंकाई गेंदबाज अभी तक प्रभाव छोड़ने में विफल रहे हैं।

इसमें से चुनी जाएगी भारत की प्लेइंग 11: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेट कीपर), उमा छेत्री (विकेट कीपर), पूजा वस्त्रकार, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, दयालन हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, सजाना सजीवन।

श्रीलंकाः चमारी अटापट्टू (कप्तान), अनुष्का संजीवनी, हर्षिता समरविक्रमा, हासिनी परेरा, अमा कंचना, उदेशिका प्रबोदानी, विशमी गुणरथने, काव्या कविंदी, इनोशी प्रियदर्शनी, सुगंधिका कुमारी, अचिनी कुलसूर्या, कवीशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, सचिनी निसानसाला, शशिनी गिम्हानी।

सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली (ईएमएस)। फिच रेटिंग्स ने कहा कि भारत का चुनाव बाद का बजट इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। गठबंधन में शामिल दलों की मांग के बावजूद नई सरकार राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर टिकी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केंद्र के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत कर दिया है। फरवरी के अंतरिम बजट में लक्ष्य 5.1 प्रतिशत तय किया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार का राजकोषीय घाटा लक्ष्य, रेटिंग एजेंसी के 5.4 प्रतिशत के अनुमान से काफी कम है। रेटिंग एजेंसी ने जनवरी 2024 में भारत की बीबीबी- रेटिंग की पुष्टि करते समय राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद का 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। फिच ने कहा ?कि ऐसा लगता है कि सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के अपने लक्ष्य को भी हासिल कर लेगी।

सरकार जारी करेगी 18,500 करोड़ का पेपर गोल्ड

नई दिल्ली (ईएमएस)। सरकार ने गोल्ड बॉन्ड पर 38 फीसदी कटौती की है, यह कटौती बांड की कीमत में या ब्याज दर में हो सकती है, जो निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बेहतर विकल्पों के आने से निवेशकों की इसमें रुचि कम हो गई है। अब सरकार 2024-25 में 18,500 करोड़ का पेपर गोल्ड जारी करने की योजना बना रही है। अंतरिम बजट में 29,638 करोड़ का अनुमान लगाया गया था और 2023-24 में 26,852 करोड़ रखा गया था। अधिकारी ने बताया कि इसमें निवेशकों की मांग, अन्य निवेश प्रोडक्ट और ग्लोबल इकॉनमी में अनिश्चितताएं शामिल हैं। फरवरी में अंतरिम बजट के बाद से स्थिति बदल गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत 2015 में हुई थी। बाजार के जानकारों ने बताया ?कि कई बेहतर निवेश विकल्पों की उपलब्धता और गोल्ड बॉन्ड की तुलना में अधिक लाभ दायकरिटर्नदेनेवाले विकल्पों के कारण निवेशकों की रुचि गोल्ड बॉन्ड में कम हो गई है। उन्होंने बताया कि कई रिटले निवेशक अब इक्विटी में अपना निवेश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन की योजना सितंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक परिवहन प्रोत्साहन योजना (ईएमपीएस) को दो महीने के लिए बढ़ाकर के साथ कुल परिव्यय को भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया। इस योजना को इस साल मार्च में भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देना है।

ईएमपीएस योजना मूल रूप से एक अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक चलने वाली थी, जिसका कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपये था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस योजना को दो महीने 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा योजना का परिव्यय भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य सरकार की हरित पहलों को आगे बढ़ाना और देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण परिवेश के विकास को बढ़ावा देना है।

इस योजना के तहत पात्र ईवी श्रेणियों में पंजीकृत ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट सहित इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन शामिल हैं। आम लोगों के लिए किफायती और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प मुहैया कराने पर जोर देने के साथ यह योजना मुख्य रूप से उन ई-दोपहिया और ई-तिपहिया पर लागू होगी जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत हैं। इसके अलावा निजी या कॉरपोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत ई-दोपहिया भी योजना के तहत पात्र होंगे।

भगोड़ा माल्या तीन साल तक भारतीय बाजारों में नहीं कर सकेगा प्रवेश

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या पर तीन साल तक भारतीय बाजारों में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई 2006 से 2008 के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के रास्ते से भारतीय प्रतिभूतियों में पैसा लगाने के लिए की गई है। पूर्व शराब कारोबारी को तीन साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी से जुड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। सेबी ने माल्या की सभी सिक्योरिटी होल्डिंग्स को फ्रीज करने का आदेश दिया है, जिसमें म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी शामिल हैं। माल्या ने मैटरहॉर्न वेंचर्स नाम की एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) कंपनी के जरिए अपने ही समूह की भारतीय कंपनियों के शेयरों में अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार किया। इस तरह से उन्होंने प्रतिभूति बाजार में अपने निवेश की असली पहचान को छिपाया। सेबी ने कहा कि माल्या ने अपनी पहचान छिपाकर मैटरहॉर्न वेंचर्स नाम की एफपीआई कंपनी के जरिए निवेश किया, जो भारतीय कंपनियों के शेयरधारकों के हित के खिलाफ था। सेबी के आदेश के अनुसार इस एफपीआई कंपनी का इस्तेमाल हरबर्टसन्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स (यूएसएल) जैसी शराब कंपनियों के शेयरों में लेन-देन के लिए किया गया। सेबी ने पाया कि मैटरहॉर्न वेंचर्स के पास हरबर्टसन्स के 9.98 प्रतिशत शेयर थे, जो वास्तव में प्रमोटर श्रेणी के थे और पूरी तरह से माल्या द्वारा फंडेड थे।

विवाहित और महिला कारोबारियों को इंट्रा-डे ट्रेड में कम हुआ घाटाः सेबी

नई दिल्ली (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार में दैनिक आधार पर शेयर की खरीद-बिक्री (इंट्रा-डे) करने वाले ??विवा?हित कारोबारी अविवाहित कारोबारियों के मुकाबले कहीं बेहतर नतीजे प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इसके अलावा इंट्रा-डे कारोबार के मामले में महिलाएं पुरुष कारोबारियों के मुकाबले अधिक मुनाफा कमाती हैं। यह विश्लेषण इक्विटी नकदी खंड में इंट्रा-डे कारोबार को लेकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक अध्ययन में सामने आया है। एक कारोबारी सत्र में ही किसी शेयर की खरीद और बिक्री दोनों गतिविधियों का संचालन इंट्रा-डे कारोबार कहा जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक विवाहित और एकल कारोबारियों के अलावा पुरुष और महिला कारोबारियों के बीच सौदा संबंधी व्यवहार और परिणामों के बीच बहुत अंतर है। सेबी ने पाया है कि इक्विटी नकदी खंड में इंट्रा-डे कारोबार करने वाले विवाहित लोग कई प्रमुख क्षेत्रों में अविवाहितों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वित्त वर्ष 2018-19, 2021-22 और 2022-23 के दौरान अविवाहित कारोबारियों के मुकाबले विवाहित कारोबारियों ने इंट्रा-डे सौदों में कम नुकसान उठाया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 75 प्रतिशत अविवाहित कारोबारी घाटे में रहे जबकि घाटे में रहने वाले विवाहित कारोबारियों की संख्या 67 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त विवाहित कारोबारियों ने कहीं अधिक संख्या में सौदे भी किए। सेबी के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू पुरुष और महिला कारोबारियों का तुलनात्मक विश्लेषण है। इन सभी वर्षों में लगातार लाभ कमाने वालों के बीच महिला कारोबारियों का पुरुष कारोबारियों की तुलना में अधिक अनुपात था। सेबी ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि कारोबारियों का आयु समूह जितना कम होगा, उनमें नुकसान उठाने वालों का अनुपात उतना ही अधिक होगा। वहीं अधिक आयु समूह वाले कारोबारियों में नुकसान उठाने वालों का अनुपात कम था।

अमेरिका में अन्य देशों की तुलना मे लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर कम

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने एक ओर इंट्राडे ट्रेडिंग पर लगने वाले शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है, वहीं लंबी अवधि के ?निवेश पर लगने वाले लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दरों को भी बढ़ा दिया है लेकिन क्या लांग टेरन कैपिटल गेन पर टैक्स केवल भारतीयों को ही देना पड़ता है, क्या अन्य देशों में भी इस टैक्सेशन से जुड़े कुछ नियम हैं? गौरतलब है ?कि बजट 2024 के प्रस्ताव के तहत शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। वहीं लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दर को भी 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है। सरकार ने लांग टर्म में सोने और प्रॉपर्टी जैसे फिजिकल एसेट्स पर जो इंडेक्सेशन की सुविधा मिलती थी उसे भी खत्म कर दिया है। हालांकि, एक राहत है कि लांग टर्म कैपिटल गेन में अब 1.25 लाख रुपये तक का मुनाफा टैक्स मुक्त हो गया है। अमेरिका में दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर कम है। यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर सामान्य है जबकि लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अधिकतम 20 प्रतिशत है। वहीं यहां चल और अचल संपत्ति की बिक्री पर होने वाले फायदे पर सरकार टैक्स लेती है, जो कि 20 फीसदी है। वहीं शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की खरीद बिक्री पर होने वाले फायदे पर सरकार टैक्स नहीं वसूलती है। जापान में एसेट क्लास के अनुसार टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। जैसे शेयर की बिक्री, जमीन और मकान की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अधिकतम 20 प्रतिशत है जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 39 प्रतिशत है। ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स लगता है। इस पर बहुत कम दर से टैक्स वसूला जाता है। यदि कोई ऑस्ट्रेलियाई नागरिक 12 महीने से ज्यादा के लिए कोई निवेश करता है, तो उसके कैपिटल गेन प्रॉफिट के 50 प्रतिशत पर ही उसे टैक्स देना होता है। सिंगापुर में किसी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है।

विएंतियाने में कई देशों के विदेश मंत्रियों से मिल रहे जयशंकर

विएंतियाने (लाओस)। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय आसियान की बैठकों में भाग लेने लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी विएंतियाने में हैं। शनिवार को उन्होंने अपने तुर्किये समकक्ष हकन फिदान के साथ बैठक की।

वहीं, रूसी विदेश मंत्रालय ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर आसियान कार्यक्रमों के मौके पर मुलाकात करते दिख रहे हैं। इससे पहले जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की और विशेष रणनीतिक साझेदारी पर व्यापक चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर में अपने समकक्ष और प्रिय मित्र विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात कर उनके साथ अच्छी बातचीत की।

बता दें कि जयशंकर ने ब्रुनेई के अपने समकक्ष दातो हाजी एरीवान के साथ भी बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक लोगो लांच किया। जयशंकर ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध और भी मजबूत होने वाले हैं। उन्होंने लाओस के गृह मंत्री विलायवो एनजी बौडाखम, उद्योग और वाणिज्य मंत्री मलाइथोंग कोमासिथ, विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष सान्या प्रसुथ और विशेष दूत अलौंकियो किट्टीखौन से भी मुलाकात की।

खाई में गिरी कार,8 की मौत

अनंतनाग (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के डक्सुम में रोड एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 5 बच्चे, 2 महिलाएं और एक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हादसा सिंथन-कोकरनाग रोड पर हुआ। कोकरनाग के एसडीएम सुहेल अहमद के मुताबिक, दक्षिण कश्मीर के डक्सुम के पास प्राइवेट कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। सभी मृतकों को कोकरनाग के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

गोल्डी-अशोक समेत 16 कंपनियों के मसाले खाने योग्य नहीं

सब्जी मसालों में मिले कीड़े और पेस्टिसाइड्स, बिक्री पर रोक लगाई

कानपुर (ईएमएस)। जिन मसालों को आप खाते हैं, उससे आपकी सेहत बिगड़ रही है। गोल्डी, अशोक, भोला सब्जी मसाले समेत 16 कंपनियों के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) का कहना है- कंपनियों के कई प्रोडक्ट खाने योग्य नहीं हैं।

दरअसल, एफएसडीए के अफसरों ने इसी साल मई में कानपुर में मसालों की कंपनियों पर छापा मारा था। 16 कंपनियों के अलग-अलग मसालों के 35 प्रोडक्ट के सैंपल लेकर जांच के लिए आगरा भेजे थे। इनमें से 23 की रिपोर्ट सामने आई है। इनमें पेस्टिसाइड और कीटनाशक (इंसेक्टिसाइड) की मात्रा काफी अधिक पाई गई। कीड़े भी मिले हैं। इसके बाद एफएसडीए ने मसालों के इन प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। गोल्डी मसाले के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता सलमान खान हैं।

गरम मसाला, बिरयानी और सांभर मसाला में मिली कमी

मसालों की ज्यादातर कंपनियां कानपुर में हैं। एफएसडीए के अफसरों ने कानपुर के दादानगर की शुभम गोल्डी मसाला कंपनी से सैंपल कलेक्ट किए थे। उनमें सांभर मसाला, चाट मसाला और गरम मसाला अनसेफ मिला है। यह कंपनी गोल्डी ब्रांड के लिए प्रोडक्ट बनाती है। इसी तरह अशोक मसालों की दो कंपनियों के प्रोडक्ट में कमियां मिलीं। इनके प्रोडक्ट- धनिया पाउडर, गरम मसाला और मटर पनीर मसाला खाने योग्य नहीं मिला। इसी तरह भोला मसाले के प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लोकल लेवल पर बिकने वाली 14 अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट में हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं। इन कंपनियों के हल्दी पाउडर में भी पेस्टिसाइड्स मिला है।

13 मसाला फैक्ट्रियों पर रेड की गई थी

सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया- अशोक, गोल्डी ब्रांडेड मसालों समेत अन्य कंपनियों के 23 नमूनों में कीड़े, दूषित पदार्थ (पेस्टिसाइड्स) मिला है। एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के नमूने फेल होने के बाद शासन के निर्देश पर सैंपल लिए गए थे। खाद्य एवं औषधि विभाग ने मई में अभियान चलाकर शहर की 13 मसाला फैक्ट्रियों पर रेड की थी।

कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा

उन्होंने बताया- अलग-अलग कारखानों से 35 सब्जी मसालों के नमूने लिए थे। सभी जांच के लिए लैब भेजे गए थे। अब खाद्य विभाग जांच की रिपोर्ट के मसालों के सैंपल फेल मिले हैं। उनके मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक न होने पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उनके खिलाफ [illegible] सिटी कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा। इसके बाद सभी पर जुर्माना तय किया जाएगा।

खतरनाक कीटनाशक कार्बेडाजिम मिला

16 सैंपल में खतरनाक कीटनाशक और 7 में माइक्रो बैक्टीरिया मिले हैं। पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में मसालों में जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए हैं। साथ ही कार्बेंडाजिम भी मिला है, जिसका इस्तेमाल फफूंदी नियंत्रण के लिए होता है। कार्बेंडाजिम के इस्तेमाल से सेहत पर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दिल और गुर्दे पर खतरनाक असर पड़ता है। बांझपन और अन्य प्रजनन समस्याएं हो सकती हैं। एक अन्य नामचीन मसाले में प्रोपरगाइट मिला है। यह एक एराकिसाइड है। इसका इस्तेमाल खेतों में कीड़ों से फसलों की रक्षा के लिए किया जाता है। विशेष रूप से इसका इस्तेमाल मकड़ी के खिलाफ होता है।

पाकिस्तान का कराची दुनिया का दूसरा सबसे जोखिम वाला शहर

कराची (ईएमस)। पाकिस्तान आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि टूरिस्ट आए, जिससे उसकी कमाई हो सके। लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदों पर एक रिपोर्ट ने पानी फेर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कराची शहर दुनिया के दूसरे सबसे जोखिम वाले शहरों में से एक है। कराची को 100 में से 93.12 नंबर के साथ पर्यटकों के लिए दूसरा सबसे जोखिम भरा शहर माना गया है। फोर्ब्स एडवाइजर की तीन सबसे जोखिम भरे शहरों की सूची जारी की गई।

बेनेजुएला के कराकस के बाद कराची दूसरे स्थान पर था। कराकस का स्कोर 100 था। म्यांमार का यांगून 100 में से 91.67 स्कोर के साथ तीसरा सबसे खतरनाक शहर है। रिपोर्ट में सबसे खतरनाक दूसरा शहर होने का कारण उच्च व्यक्तिगत सुरक्षा जोखिम, अपराध, हिंसा, आतंकवादी खतरों, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक कमजोरियों से जोखिम है। रिपोर्ट कहती है कि कराची को अमेरिकी विदेश विभाग से दूसरी सबसे खराब यात्रा सुरक्षा रेटिंग मिली है, जो यात्रा पर पुनर्विचार करने को कहता है।

फोर्ब्स एडवाइजर ने कहा कि पर्यटकों के लिए सबसे अधिक और सबसे कम जोखिम वाले शहरों की सूची बनाने के लिए, सात प्रमुख मैट्रिक्स में दुनिया के 60 शहरों की तुलना की गई। कराची बार-बार नहीं रहने लायक शहरों की सूची में आता रहा है। 2017 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से कराची को दुनिया के सबसे कम सुरक्षित शहरों में नामित किया गया था। दुनिया के खतरनाक शहरों की ही तरह फोर्ब्स एडवाइजर की ओर से सबसे सुरक्षित शहरों की भी लिस्ट सामने आई है। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में सिंगापुर है। सिंगापुर को 100 में से शून्य अंक मिले हैं। जापान का टोक्यो दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं कनाडा का टोरंटो शहर तीसरा सबसे सुरक्षित शहर है।

कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग में 130 इमारतें हुई स्वाहा, हजारों लोगों ने घर छोड़े

सैक्रामेंटो (ईएमएस)। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भयंकर आग में करीब 130 मकान आग में जलकर स्वाहा हो गए हैं। जबकि हजारों लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो के उत्तर में चिको के पास बुधवार दोपहर से शुरू हुई आग शुक्रवार सुबह तेजी से फैली। इसने 164,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया।आंकड़ों के अनुसार, आग ने पहले ही 134 इमारतों को नष्ट कर दिया है और 4 हजार 200 से ज्यादा को खतरा है। शुक्रवार सुबह तक केवल तीन प्रतिशत पर ही काबू पाया जा सका था। कैल फायर ने शुक्रवार को अपने लेटेस्ट अपडेट में कहा, आग तेजी से फैल रही है। आग वाले क्षेत्र में इस समय तेज हवाएं चल रही हैं और कम आर्द्रता के कारण रेड फ्लैग चेतावनी जारी की गई है।

आग कुछ घास, झाड़ियों, मिश्रित लकड़ी और मृत वनस्पतियों में जल रही है।इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने चिको निवासी 42 वर्षीय रॉनी डीन स्टाउट सेकंड नामक व्यक्ति को जानबूझकर आग लगाने के संदेह में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि आग तब लगी जब एक जलती हुई कार को एक नाले में धकेल दिया गया। इस कथित कृत्य के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है। पार्क फायर के तेजी से फैलने के कारण बुटे काउंटी और पड़ोसी तेहामा काउंटी में बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला गया। बुटे काउंटी के शेरिफ कोरी होनिया ने बताया कि लगभग 4,000 निवासियों को खाली करने का आदेश दिया गया है, जिनमें चिको के 400 निवासी भी शामिल हैं।

अरे ये क्या..........इराक गए 50 हजार पाकिस्तानी गायब

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान से धार्मिक यात्रा के लिए इराक गए करीब 50 हजार लोग गायब हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार में धार्मिक मामलों के मंत्री चौधरी सालिक हुसैन ने इसकी जानकारी दी है। चौधरी ने माना है कि इराक से करीब 50,000 पाकिस्तानी तीर्थयात्री वापस नहीं लौटे और वहीं गायब हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसके पीछे की वजह और उनकी ओर से की गई कार्रवाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। दूसरी ओर इराकी सरकार का कहना है कि लापता पाकिस्तानी उनके देश में अवैध रूप से काम करने के लिए रुक रहे हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर साल लाखों विदेशी तीर्थयात्री इराक आते हैं। खासतौर से अरबाईन और आशूरा पर शिया मुस्लिम इराक आते हैं। शियाओं के लिए अरबाईन की तीर्थयात्रा खास महत्व रखती है, क्योंकि ये कर्बला की लड़ाई में पैगंबर मुहम्मद के नाती हुसैन की शहादत को चिह्नित करती है। यहां दुनियाभर से लोग आते हैं और ये संख्या करोड़ों में होती है। पाकिस्तान के शिया अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य उन लोगों में से हैं, जो नियमित रूप से इराक आकर तीर्थयात्रा में भाग लेते हैं।

इराक के श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री अहमद अलअसदी ने कहा कि उनकी सरकार उन रिपोर्ट की जांच करेगी, जो लापता लोगों के उनके देश में अवैध रूप से काम करना का इशारा करती हैं। उन्होंने कहा, पिछले दिनों इराक में विभिन्न देशों से पर्यटकों की आमद देखी गई है, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इराक दुनिया के सभी पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन स्थानीय कानूनों और नियमों का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में इराक में 688 पाकिस्तानी रह रहे थे लेकिन जमीन पर यह संख्या बहुत अधिक होने का संकेत है। इस पर दोनों देशों की सरकारों का भी ध्यान है।

पापुआ न्यू गिनी में नरसंहार, 50 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा

-आधी रात को 30 लोगों की गैंग गांव में घुसी और कत्लेआम को अंजाम दिया, रात भर पड़े रहे कई शव मगरमच्छ खा गए

पापुआ न्यू गिनी (ईएमएस)। इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित पापुआ न्यू गिनी में हैरान करने वाला नरसंहार हुआ है। यहां आधी रात अज्ञात लोग गांव में घुसे और सो रहे 50 ग्रामीणों का कत्ल कर दिया। रातभर पड़े रहे शवों में कईयों को मगरमच्छ खा गए। रिपोर्टों के अनुसार, मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और युवा शामिल हैं। इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पापुआ न्यू गिनी के उत्तरी हिस्से में दूर दराज के तीन गांवों में एक गिरोह के हाथों कम से कम 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। उन्होंने कहा है कि ये संख्या 50 के पार भी जा सकती है क्योंकि और कई लोग लापता हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त वोल्कर तुर्क ने आधिकारिक बयान में बताया कि हमले 16 जुलाई और 18 जुलाई को हुए थे। उन्होंने कहा मैं पापुआ न्यू गिनी में घातक हिंसा के अचानक फैलने से भयभीत हूं। यह हिंसा भूमि और झील के स्वामित्व और इसके इस्तेमाल संबंधी विवाद का परिणाम प्रतीत होती है। तुर्क ने बताया कि कम से कम 26 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 16 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा ''यह संख्या बढ़ कर 50 से अधिक हो सकती है क्योंकि स्थानीय अधिकारी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा घरों को जला दिए जाने कारण 200 से अधिक ग्रामीण अन्यत्र चले गए है।'दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र के ईस्ट सेपिक प्रांत के कार्यवाहक प्रांतीय पुलिस कमांडर जेम्स बाउगेन ने शुक्रवार को 'ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प' को बताया ''घटना बहुत भयावह थी। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि वहां बच्चे, पुरुष व महिलाओं की लाशें पड़ी थीं। उन्हें 30 युवकों के एक समूह ने मार डाला। बाउगेन ने बताया कि गांवों के सभी घर जला दिए गए हैं और शेष ग्रामीण पुलिस थाने में शरण लिए हुए हैं। बाउगेन के अनुसार, ग्रामीण हमलावरों का नाम बताने से भी डर रहे हैं। उन्होंने बताया ''रात में कुछ शवों को पास के दलदल के मगरमच्छों ने निवाला बना लिया। हमने केवल वह जगह देखी जहां उन्हें मारा गया था। लोगों के सिर काट दिए गए थे।'' बाउगेन ने बताया कि हमलावर छिप गए हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

अंतरिक्ष में फंसी सुनीता व विल्मोर की अभी नहीं होगी वापसी, नासा ने दिया अपडेट

वाशिंगटन,(ईएमएस)। कई दिनों से अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को लेकर सभी परेशान है कि वह कब वापस लौटेंगी। इसको लेकर नासा ने नया अपडेट दिया है। सुनीता सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर जुलाई में पृथ्वी पर नहीं लौटेंगे। नासा ने कहा कि उनके बोइंग कैप्सूल में आई दिक्कतों को इंजीनियर के दूर करने तक वे वहीं रहेंगी। स्टारलाइनर टीम अब अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए डेटा की समीक्षा कर रही है।

न्यू मैक्सिको में नासा की व्हाइट सैंड्स टेस्ट सुविधा में आरसीएस थ्रस्टर परीक्षण ने मूल कारण मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की और नाममात्र अनडॉक और लैंडिंग के लिए उड़ान तर्क को अंतिम रूप देने में मदद की। मार्क नैप्पी ने कहा कि मुझे यकीन है कि हमारे पास चालक दल को वापस लाने के लिए एक अच्छा वाहन है।

इस सप्ताह के अंत में 28 आरसीएस थ्रस्टर्स में से 27 को गर्म करने की योजना बनाई गई है, जबकि अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में सुरक्षित रूप से डॉक किया गया है। इस परीक्षण का उद्देश्य थ्रस्टर्स के प्रदर्शन को सत्यापित करना और अतिरिक्त हीलियम रिसाव डेटा इकट्ठा करना है, जो 6 जून को अंतरिक्ष यान के आगमन के बाद से स्थिर बना हुआ है।

बता दें 6 जून को 'कैप्सूल' के अंतरिक्ष स्टेशन के पास पहुंचने पर पांच थ्रस्टर में गड़बड़ी आ गई। तब से चार को चालू किया जा चुका है। स्पेस शटल के सेवा से हटने के बाद, नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष स्टेशन पर आवाजाही के लिए निजी कंपनियों को काम पर लगा दिया है, जिसके लिए बोइंग और स्पेसएक्स को अरबों डॉलर का भुगतान किया गया है। यह बोइंग की पहली परीक्षण उड़ान थी जिसमें चालक दल सवार था। स्पेसएक्स 2020 से मानव को अंतरिक्ष में ले जा रहा है।

भारत ने मालदीव को दी राहत......कर्ज फिलहाल स्थगित किया

मोहम्मद मुइज्जू ने बताया फूड कोटा भी बढ़ाया

माले (ईएमएस)। भारत ने मालदीव को राहत देकर 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का कर्ज फिलहाल स्थगित किया है। भारत सरकार ने मालदीव का फूड कोटा भी बढ़ाने का फैसला लिया है। मालदीव के 59वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने खुद ये जानकारी दी है। मुइज्जू ने कहा कि भारत ने पहले ही 50 मिलियन डॉलर का कर्ज पोस्टपोन कर दिया है। साथ ही भारत सरकार ने फूड कोटा भी अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पद संभालने के बाद भारत विरोधी रुख दिखाया था लेकिन कुछ समय बाद उनके तेवर बदल गए थे। इस साल मार्च में मुइज्जू ने भारत को मालदीव का निकट सहयोगी कहते हुए ऋण राहत प्रदान करने का आग्रह किया था। बीते साल के अंत तक मालदीव पर भारत का करीब 400.9 मिलियन डॉलर बकाया था।

हालांकि दुबई में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उनके रुख में बदलाव दिखा था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मालदीव ने भारत से महत्वपूर्ण ऋण लिया है, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था के वहन से कहीं अधिक है। इसके बाद हम मालदीव की आर्थिक क्षमताओं के अनुसार ऋण चुकाने के विकल्प तलाशने के लिए भारत सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस साल मई में भारत ने मालदीव को 5 करोड़ डॉलर का बजट सपोर्ट भी दिया था।

जहाज के मलबे में मिली बेशकीमती शैंपेन और अरबों डॉलर का खजाना

वॉशिंगटन (ईएमएस)। बाल्टिक सागर में स्वीडन के तट पर खोज गोताखोरों की टीम ने जहाज 19वीं सदी का एक जहाज खोज लिया है। लंबे समय से पानी में डूबा यह जहाज लग्जरी शराब से भरा हुआ है। मलबे को खोजने वाली बाल्टिकटेक गोताखोरी टीम के लीडर टोमाज स्टैचुरा ने बताया कि जहाज का मलबा शैंपेन, मिनरल वाटर और चीनी मिट्टी के बर्तनों से भरा हुआ है। फर्म की वेबसाइट के मुताबिक वह बाल्टिक सागर में सबसे सक्रिय मलबा गोताखोरों में से एक है और अब तक हजारों मलबे की तस्वीरें ली है।

लेकिन यह हालिया खोज अलग थी। उन्होंने बताया कि इस जहाज पर लगभग 100 बोतलें मिली हैं। स्टैचुरा ने कहा, मैं 40 वर्षों से गोता लगा रहा हूं और अक्सर ऐसा होता है कि एक या दो बोतलें होती हैं। लेकिन इतने ज्यादा माल के साथ हमने मलबे को पहली बार खोजा है। उन्होंने कहा कि यह खोज काफी हद तक एक संयोग भी था, क्योंकि गोताखोर वर्षों से डूबे हुए जहाजों की तलाश में समुद्र तल में खोजबीन कर रहे हैं।

स्टैचुरा ने कहा, हम सिर्फ नए स्थानों की जांच कर रहे थे, जिन्हें मैं वर्षों से इकट्ठा कर रहा था। तभी हमें यह मलबा मिला। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस पर कुछ भी महत्वपूर्ण होगा और यहां तक कि एक पल के लिए झिझक भी हुई कि क्या गोता लगाना चाहिए? टीम की वेबसाइट के एक पोस्ट के मुताबिक दो सदस्य गोता लगाने के लिए दृढ़ थे, लेकिन जब वह गए तो पूरे दो घंटे तक जहाज के करीब रहे। जहाज का मलबा बेहद अच्छी स्थिति में था और इस पर प्रचुर मात्रा में सामान भरा था।

एक सही फैसले ने कैसे बदल दी महिला की पूरी जिंदगी

-वजन घटाने के साथ ही फाइनेंशिल लाइफ भी सुधारने की अनूठी कहानी

तुर्किये (ईएमएस)। वजनदार महिला के एक सही फैसले ने कैसे उसकी पूरी जिंदगी बदलकर रख दी। महिला ने वजन घटा कर लाइफस्टाइल बदलने के साथ ही अपनी फाइनेशिल लाइफ भी सुधारने का अनूठी कहानी सुनाई है। महिला का वजन 152 किलो और साइज 26 हो गया था।

चेस्टर की रहने वाली 31 वर्षीय लॉरेन इवेंस को हमेशा से ही अपने वजन को नियंत्रित करने में कठिनाई होती रही है। तीन बच्चों की मां ने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ संघर्ष किया। अपनी स्थिति के कारण, लॉरेन के पास यूनिवर्सल क्रेडिट और पीआईपी का दावा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए बेताब वह खुद को अस्पताल से अंदर और बाहर होता देखती थी। तभी लॉरेन ने अपने पास मौजूद थोड़े से पैसे बचाने का फैसला किया और गैस्ट्रिक स्लीव लगवाने के लिए तुर्किए की 2,300 पाउंड की यात्रा बुक की और इस फैसले ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह बेरोजगार और ज़्यादा वजन वाली से एक आर्थिक रूप से 'आरामदायक' टर्की-सर्जरी इन्फ्लुएंसर बन गई है, जिसके पास अब एक कंपनी के शेयर भी हैं। लॉरेन ने अब सर्जरी पर 20,000 पाउंड खर्च कर दिए हैं। उन्होंने कहा, ''जब मैंने पहली बार तुर्कीये की यात्रा शुरू की थी, तो मैं सरकारी मदद पर निर्भर पर थी।

आज लॉरेन के टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर कुल 65,000 फ़ॉलोअर हैं, जहां वह नियमित रूप से प्रशंसकों, ज़्यादातर बैरिएट्रिक 'समुदाय' के लोगों को अपनी सर्जरी के प्रयासों के बारे में अपडेट करती है। इसके बाद लॉरेन को तुर्की के उन ब्रांडों ने नोटिस किया, जो एक नए मेडिकल टूरिज्म उद्योग से लाभ कमा रहे हैं, जिसमें अनुमानित 1.2 मिलियन लोग कॉस्मेटिक काम के लिए सालाना मध्य पूर्वी देश आते हैं। और वह भी यूके के लोग जितने भुगतान करने की उम्मीद करते हैं, उससे बहुत कम कीमत पर।

गुजरात में कैंसर, किडनी सहित ६६५ नई दवाईयां निशुल्क मिलेंगी

अहमदाबाद, २७ जुलाई । गुजरात सरकार ने जीवन रक्षक दवाइयों की सूची में वृद्धि करने की घोषणा की है। अब तक इस सूची में ७१७ दवाई शामिल थीं, अब इस सूची में ६६५नई दवाईयों को शामिल किया गया है।

गुजरात सरकार ने जीवन रक्षक दवाइयों की सूची में वृद्धि करने की घोषणा की है। अब तक इस सूची में ७१७ दवाई शामिल थीं, अब इस सूची में ६६५नई दवाईयों को शामिल किया गया है। इसके चलते इस सूची में शामिल दवाईयों की संख्या बढ़कर १३८२ हो गई है। इस निर्णय से १२ तरह की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को लाभ मिलेगा। इसमें कैंसर, किडनी, के अलावा बीपी, हृदय रोग की दवाइयां भी शामिल हैं। ये दवाएं राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों से लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सिविल अस्पतालों तक मुफ्त उपलब्ध होंगी।

स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने जीवन रक्षक आवश्यक दवा सूची (ईडीएल) में २०२४-२५ में ६६५ नई दवाएं शामिल की हैं। प्रदेश के हर मरीज को सर्वोत्तम इलाज और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उनके अनुसार हर वर्ष जरूरी दवाई की सूची को संशोधित किया जाता है। इस वर्ष जोड़ी गई नई दवाओं में कैंसर, संक्रमण, हृदय संबंधी, मधुमेह, बीपी की दवाइयां शामिल हैं। किडनी रोग से जुड़ी जीवन रक्षक दवाएं भी इसमें शामिल की गई हैं।मंत्री के अनुसार प्राइमरी चिकित्सा के लिए ३०८, दूसरे स्तर की चिकित्सा के लिए ४९५ तथा तीसरे स्तर की चिकित्सा के लिए १३४९ दवाइयां हैं। इसके अलावा विशेष चिकित्सा के लिए ३३ दवाएं सूची में शामिल हैं। इनमें ५४३ टैबलेट, ३३१ इंजेक्शन, ३०० सर्जिकल और २०८ अन्य दवाएं शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि वर्ष २०२२-२३ की दवा सूची में २४ तरह की दवाई हृदय संबंधी उपचार की थी जिसे इस बार बढ़ाकर ११७ कर दिया है। संक्रमण रोधी दवाइयों को १२० से बढ़ाकर १९९ कर दिया है। कैंसर रोधी दवाई की लिस्ट १७ से बढ़ाकर ४७ की गई है , जबकि न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग संबंधी दवाई की सूची ५२ से बढ़ाकर १२३ की गई है।

वाइफ को हर तीन महीने में कोर्ट में पेश करनी होगी ये रिपोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी को कोमा पीड़ित पति का संरक्षक बनाया

अहमदाबाद, २७ जुलाई । गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी को शर्तों के साथ संपत्ति प्रबंधन की अनुमति है क्योंकि कोमा में चल रहे पति फिलहाल निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने पांच साल से कोमा में चल रहे एक मरीज की पत्नी को उसका संरक्षक नियुक्तकरने और पति के इलाज के लिए उसकी चल-अचल संपत्ति के प्रबंधन की अनुमति दी है। मरीज की सही ढंग से हो तीमारदारी इसलिए पत्नी कोज, मरीज की सही देखभाल के लिए नियुक्तहोंगे अधिकारी कोर्ट ने व्यक्ति को कोमा में रहने तक यह अनुमति दी है और संपत्ति प्रबंधन के बारे में कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जस्टिस संगीता के. विसेन ने कोमा पीड़ित करणसिंह डोडिया की पत्नी अंजूबेन की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट का यह फैसला इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि मौजूदा कानूनों में कोमा से पीड़ित व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने २०१९ से कोमा में चल रहे करणसिंह डोडिया की मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाया। कोर्ट ने कहा कि मरीज खुद की देखभाल करने या कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है।

अपने आदेश में कोर्ट ने पत्नी को संरक्षक घोषित करते हुए कहा कि उसे हर तीन महीने में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश कर संपत्तियों के बारे में किए गए लेन-देन, प्राप्त धन और इसे रोगी के भरण-पोषण के लिए उसके उपयोग का विवरण देना होगा। मरीज की सही ढंग से हो तीमारदारी इसलिए पत्नी कोज, मरीज की सही देखभाल के लिए नियुक्तहोंगे अधिकारी साथ ही राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी यह नजर रखेगा कि मरीज की सही देखभाल हो रही है या नहीं?

राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन में गुजरात की 150 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी

अहमदाबाद (ईएमएस) अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा सोमवार, 29 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली के जंतरमंतर से देशव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है। इस आंदोलन में गुजरात से 150 से ज्यादा महिलाएं दिल्ली में आंदोलन का हिस्सा बनेंगी। राष्ट्रव्यापी इस आंदोलन की तीन प्रमुख मांगें हैं। इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जेनीबेन ठुम्मर ने कहा कि पहली मांग राजनीतिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी है।

इस राजनीतिक न्याय एवं राजनीतिक भागीदारी के तहत मांग है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानून को लागू करें, आज करें, अभी करें और अति पिछड़े वर्ग की एससी, एसटी एवं ओबीसी बहनों के साथ उनकी जगह एवं भागीदारी सुनिश्चित करें। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानून का क्रियान्वयन करें। फिलहाल संसद का सत्र चल रहा है और उस पर चर्चा कर इसे लागू किया जाए। ताकि हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में 2024 के अंत तक होनेवाले चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके। दूसरी मांग है आर्थिक न्याय, आज महिलाएं बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी की शिकार हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण कई महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। हमारी मांग है कि देश की आधी आबादी को महंगाई से राहत दी जाए। इस बजट में महिलाओं को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह बजट निराशा भरा रहा। महिलाओं के लिए नौकरी या महंगाई से राहत की कोई बात नहीं हुई। हमारी मांग है कि महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू की जाए। महालक्ष्मी योजना में कहा गया है कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। लगभग 8,500 रुपये प्रति माह सीधे उनके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।

हमारी मांग है कि महिलाओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए महालक्ष्मी योजना के तहत यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। सीधे उनके खातों में पैसा जमा कर उनका आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक न्याय किया जाना चाहिए। तीसरी मांग है सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार। भाजपा सरकार में महिलाओं पर अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों में कानून का भय कम होता जा रहा है।

ताजा घटना गुजरात के राजकोट जिले के आटकोट में डी.बी. पटेल एजुकेशन ट्रस्ट के दो आरोपियों परेश रादडिया और मधु टाढानी ने लड़की से रेप किया। घटना को लेकर जब पीड़ित लड़की खुद मीडिया के सामने आकर अपने लिए न्याय की मांग कर रही है तो सरकार सिर्फ खोखले दावे और झूठे आश्वासन दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर फास्टट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। पिछले एक महीने में टेट-टैट-एलआरडी महिलाएं जब गांधीनगर में अपने हक, अधिकार और न्याय के लिए शांतिपूर्ण धरना दे रही थीं तब पुलिस और सरकार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें हिरासत में ले लिया, जो निंदनीय और अमानवीय है। लोकतंत्र में महिलाओं को आंदोलन करने का अधिकार है। हम गांधीवादी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस आंदोलन में उठने वाली हर आवाज को उठाएंगे। जेनीबेन ठुम्मर ने कहा कि तीन मुख्य मांगों को लेकर दिल्ली में शुरू होनेवाला आंदोलन गुजरात में महिला कांग्रेस संगठन के माध्यम से जिला स्तर पर चलाया जाएगा और जब तक सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती तब तक महिला कांग्रेस गुजरात की महिलाओं के लिए मिलकर संघर्ष करती रहेगी।

वित्तमंत्री ने बजट के दौरान कृषि संबंधी कई बातें झूठी और फर्जी आंकड़े पेश कर संसद को गुमराह किया : कांग्रेस

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 2024-25 के बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कृषि से जुड़ी कई बातें झूठी, अधूरी और सरकारी आंकड़ों के विपरीत पेश कर संसद को गुमराह किया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी (C2+50%) केंद्र सरकार द्वारा किसानों को नहीं दिया गया है। भाजपा सरकार द्वारा परिभाषित एमएसपी है किसानों को जो वास्तव में एमएसपी (C2+50%) दिया जाता है वह नहीं है और जो लोग एमएसपी घोषित करते हैं, वे उस कीमत पर फसल खरीदने में विफल रहते हैं। इस प्रकार वित्तमंत्री ने संसद में झूठ बोलकर संसद गुमराह करने और किसानों का हक छीनने का काम किया है। 2014-2024 के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पांच कृषि-उन्मुख योजनाओं की घोषणा की, जिसमें से कुल 7,67,814 करोड़ रुपये दिए गए, जिनमें से 2,91,480 करोड़ रुपये यानी अप्रयुक्त 38% धन वापस आ गया जो भाजपा सरकार के किसान विरोधी रवैये को स्पष्ट करता है। इस प्रकार बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करके बड़ी मात्रा में धन आवंटित करने की मानसिकता केवल चुनाव जीतने के लिए ही देखी जाती है, यह देश के किसानों के लिए इन विवरणों से स्पष्ट हो गया है और भाजपा सरकार बेनकाब हो गई है। भाजपा सरकार के कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2022-23 में कुल कृषि उत्पादन के एमएसपी से ऊपर समर्थन मूल्य पर कृषि फसलें नहीं खरीदी गईं, जिससे यहां भाजपा सरकार के दावे की पोल खुल गई है। केंद्र सरकार ने कुल उत्पादन 1068 लाख टन में से केवल 187.52 लाख टन गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा है, यानि कि भाजपा सरकार के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग हैं। कोरोना फैलने के बाद भाजपा के मोदी परिवार के दिमाग नया शब्द आत्मनिर्भर भारत जोड़ा और एक बार फिर देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयोग शुरू किया। संसद में वित्त मंत्री ने एक बार फिर आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग कर संसद को गुमराह किया बजट रीडिंग में भारत लेकिन उसमें नाम बड़े और दर्शन झूठे। भाजपा सरकार पिछले 10 वर्षों में भारत को किसी भी क्षेत्र, तकनीक या उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बना पाई है। हम देश की कुल खाद्य तेल आवश्यकता का 60% आयात करते हैं, चालू वर्ष 2023-24 में 121 लाख टन खाद्य तेल और 2022-23 में 157 लाख टन खाद्य तेल (1.67 लाख करोड़ रुपये) और 2023-24 (अप्रैल से दिसंबर) में 28.40 लाख टन दालों का आयात किया गया। जबकि 2022-23 में 17.50 लाख टन का आयात किया गया। इस प्रकार भाजपा सरकार 10 वर्षों में खाद्य तेल और दालों के मामले में खुद को आत्मनिर्भर नहीं बना पाई है और वित्त मंत्री संसद में आत्मनिर्भर भारत के बारे में अलग-अलग वाक्य उछालकर संसद को गुमराह कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर पूरे देश में खूब ढोल पीटा गया और यह किसानों को धोखा देने की खतरनाक चाल है।

आज अहमदाबाद में भारी से अतिभारी वर्षा का पूर्वानुमान

अहमदाबाद (ईएमएस) मौसम विभाग ने आगामी 7 दिनों के दौरान गुजरातभर में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस दौरान राज्य में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल यानि रविवार को अहमदाबाद में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। अहमदाबाद ही नहीं वडोदरा और छोटाउदेपुर में भी अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र में अतिभारी बारिश हो सकती है। गुजरात पर दो सिस्टम के सक्रिय होने से अत्यंत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। रविवार को अरवल्ली, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा और छोटाउदेपुर में अतिभारी बारिश की संभावना है। इसके साबरकांठा, गांधीनगर, खेडा, आणंद, नर्मदा, भरुच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमण और दादरा नगर हवेली, अमरेली, भावनगर में भी भारी बारिश की संभावना है।

गुजरात कांग्रेस की राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की मांग

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात कांग्रेस ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए मौखिक घोषणा करने के बजाए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की मांग की है। साथ ही राज्य में शिक्षकों की रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम संख्या में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दो महीनों के भीतर पूर्ण करने की मांग की है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक और प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि आरटीई नियम बनने के बाद विशेषकर कक्षा 6वीं से 8वीं तक विषयवार शिक्षकों की भर्ती और बुनियादी ढांचे को तीन साल के भीतर पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन बारह साल बीत जाने के बावजूद भी राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया है। राज्य में 40 हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं और बुनियादी ढांचे के मामले में, लगभग 38,000 कक्षाओं की कमी है। जो कक्षाएँ मौजूद हैं उनमें भी बड़ी संख्या में कक्षाएं जर्जर हैं। गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने ज्ञान सहायक योजना प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 11 महीने के अनुबंध के तहत भर्ती की घोषणा की है। शिक्षकों को स्थाई करने के स्थान पर संविदा व्यवस्था लागू करने की भाजपा सरकार की योजना असंवैधानिक एवं अवैध है। शिक्षा विभाग ने स्थायी शिक्षकों की भर्ती के बजाय ज्ञान सहायकों के लिए दोबारा विज्ञापन निकाला है। टेट-टैट पास कर चुके गुजरात के हजारों युवक-युवतियां स्थायी भर्ती का सपना देख रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा संविदा आधार पर ज्ञान सहायक की भर्ती की घोषणा करना कहां तक उचित है? गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के पेज नंबर में ज्ञान सहचर योजना की घोषणा की। 22, बिन्दु क्रमांक. 517 में स्पष्ट रूप से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है, फिर अनुबंध के आधार पर ज्ञान सहायता योजना क्यों? जब स्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए व्यापक अनुरोध होते हैं, तो आक्रोश को शांत करने के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा भवन और जनसंचार माध्यमों में मौखिक घोषणा की जाती है, लेकिन मौखिक घोषणा के अनुसार आधिकारिक भर्ती नहीं की जाती है। हाल ही में पांच-पांच साल से शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे गुजरात के टेट-टैट पास युवाओं ने तत्काल भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन प्रकाशित न करने की मांग को लेकर गांधीनगर में प्रदर्शन किया था। फिर एक बार भर्ती प्रक्रिया की मौखिक घोषणा की गई, जिसे कई दिन बीत जाने के बावजूद आज तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा प्रकाशित नहीं की गई है।

पीएम मोदी के ‘विकसित भारत2047’ के संकल्प को साकार करने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध है: मुख्यमंत्री

गांधीनगर (ईएमएस) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ‘विकसित भारत2047’ के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने में गुजरात की संपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में कहा कि ‘विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात’ के ध्येय मंत्र के साथ राज्य सरकार ने ‘गुजरात2047’ डायनेमिक डॉक्यूमेंट-रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘अर्निंग वेल’ और ‘लिविंग वेल’ के दो प्रमुख स्तंभों पर आधारित इस रोडमैप के जरिए राज्य के लोगों के जीवन स्तर को सर्वोत्तम बनाने और उनकी समृद्धि को अर्थव्यवस्था में सहभागी बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन लक्ष्यों को सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से हासिल करने के लिए के लिए थिंक टैंक के रूप में गुजरात राज्य इंस्टीटयूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी-ग्रिट) की स्थापना करने की मंशा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने प्रधानमंत्री के विचार मंत्र ‘ग्यान’ यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास को आधार बनाकर ‘विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात’ का संकल्प किया है। उन्होंने कहा कि देश की आबादी में लगभग पांच फीसदी हिस्सेदारी के साथ गुजरात ने वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.3 फीसदी का योगदान दिया है। इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान देने के लिए गुजरात 2047 तक 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम गति शक्ति, स्वास्थ्य, नारी गौरव नीति, श्री अन्न (मिलेट), प्राकृतिक कृषि, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और अमृत सरोवर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य सरकार की मौजूदा उपलब्धियों और भविष्य के विजन के लिए किए जा रहे ठोस आयोजन-उपायों की विस्तृत भूमिका दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयासों से ऐसे निर्णय लेने होंगे और ऐसी नीतियां बनानी होंगी, ताकि हम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकें। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय होने चाहिए, जो देश की सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के साथ-साथ ग्लोबल सप्लाई चेन में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दर्ज करा सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इस विजन और विकसित भारत के लिए हरित विकास (ग्रीन ग्रोथ) के विचार को गुजरात आगे बढ़ा रहा है।

इस संबंध में उन्होंने आगे कहा कि जनवरी-2024 में आयोजित वाइब्रेंट समिट में गुजरात ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है, जिसका लाभ न केवल पूरे देश को बल्कि दुनिया को भी मिलेगा। यही नहीं, देश की पहली सेमीकंडक्टर चिप का भी उत्पादन भी गुजरात में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘विकसित भारत2047’ के लिए आवश्यक स्किल इकोसिस्टम को गति देने के लिए राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर्स, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे भविष्य के क्षेत्रों में आज की युवा पीढ़ी को ‘मुख्यमंत्री भविष्यलक्षी कौशल्य विकास योजना’ के माध्यम से अभी से ही प्रशिक्षित करने के प्रयासों पर फोकस किया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ग्रीन ग्रोथ के विचार को मूर्त रूप देने की दिशा में गुजरात सोलर रूफटॉप स्कीम के व्यापक कार्यान्वयन और कच्छ में निर्माणाधीन दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के माध्यम से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने कृषि और गैर-कृषि, दोनों ही क्षेत्रों को समान रूप से महत्व दिया है। प्राकृतिक खेत उत्पादों को वैश्विक निर्यात की मांग के अनुरूप बनाया गया है।

2024-25 में भारतीय रेल में नई लाइन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए 68,634 करोड़ रु. का औसत वार्षिक बजट आवंटन

2014 से 2024 तक भारतीय रेल द्वारा 31,180 किलोमीटर का उल्लेखनीय विस्तार हासिल किया गया, जिसमें नई लाइनों, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण खंडों के लिए प्रतिदिन 8.54 किलोमीटर की औसत कमीशनिंग दर है

रेलवे परियोजनाओं का सर्वेक्षण/ स्वीकृति/ निष्पादन क्षेत्रीय रेलवे-वार किया जाता है, न कि राज्य/ क्षेत्र-वार/जिला-वार, क्योंकि रेलवे परियोजनाएं राज्य की सीमाओं में फैली हो सकती हैं। इसके अलावा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पारिश्रमिक, अंतिम मील कनेक्टिविटी, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, भीड़भाड़/ संपूर्ण लाइनों के विस्तार, सामाजिक-आर्थिक अवधारणाओं आदि के आधार पर लिया जाता है, जो मौजूदा परियोजनाओं की देनदारियों, धन की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।

वर्तमान में, 651 पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के तहत भारतीय रेल पर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कुल 49,983 किलोमीटर लंबाई वाले सर्वेक्षण (नई लाइन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण) किए गए हैं, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना बनाना, लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना और औद्योगिक समूहों, बंदरगाहों, खदानों, बिजली संयंत्रों, पर्यटन और सांस्कृतिक स्थानों, कृषि क्षेत्रों आदि से कनेक्टिविटी सहित लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को दूर करना है।

01.04.2024 तक, भारतीय रेल में, कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं (187 नई लाइन, 40 गेज परिवर्तन और 261 दोहरीकरण), जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रु. है, योजना/ अनुमोदन/ निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो गई है और मार्च, 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रु. का व्यय हो चुका है।

अंबाजी जानेवाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण खबर, गब्बर रोप वे सेवा चार दिन रहेगी बंद

अहमदाबाद (ईएमएस) उत्तर गुजरात स्थित शक्तिपीठ अंबाजी के दर्शनार्थ जानेवाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अंबाजी में गब्बर रोप-वे सेवा चार दिन तक बंद रहेगी। अम्बाजी के गब्बर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रशासन ने जारी की है। जिसके मुताबिक अंबाजी गब्बर रोपवे सेवा 30 जुलाई से चार दिनों के लिए बंद रहेगी। अर्थात 2 अगस्त तक गब्बर रोपवे सेवा बंद रहेगी। रोप वे के रखरखाव के लिए अगले सप्ताह मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक रोप वे सेवा बंद रहेगी। शनिवार से रोप वे सेवा पुनः शुरू होगी।

पश्चिम रेलवे - राजकोट मण्डल

सिग्नलींग कार्य

ई-निविदा सूचना सं. DRM-RJT-24-25-SnT-E-01R1, दिनांक: 22/07/2024, **निविदा सं. DRM-RJT-24-25-SnT-E-01R1. दिनांक: 22/07/2024. कार्य का नाम:** राजकोट मण्डलः- DEN (W) राजकोट के अधिकारक्षेत्र आधिन LC सं. 169, 174, 231, 254, 267 और 272 अंतर्गत LHS/ RUB का प्रावधान करने के संबंध में सिग्नलींग कार्य। **निविदा लागत:** ₹ 83,24,529.57/- (रु. तिरासी लाख चौबीस हजार पांच सो उनत्तीस एवं सत्तानबे पैसे केवल) **जमा बयाना राशी:** ₹ 1,66,500/- (रु. एक लाख छियासठ हजार पांच सो केवल) **निविदा प्रपत्र शुल्क :** पैरा-3, GCC-जुलाई-2022 के अनुसार ₹ 00.00 **ऑन लाईन आवेदन करने की तिथि एवं समय:** दिनांक 21/08/2024 को 15:30 बजे तक। **कार्यालय का पता:** मण्डल रेल प्रबंधक (एस एण्ड टी), पश्चिम रेलवे, कोठी कम्पाउन्ड, राजकोट-360 001, वेबसाईट: www.ireps.gov.in RJT-066

हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे-अहमदाबाद

नई लाईन का निर्माण

ई-निविदा सूचना सं. DYCEC2ADIBHNDHOLERA1 **(दो पैकेट)** भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए उप मुख्य अभियंता (निर्माण)-II, पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद निम्नानुसार कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित करते है : **(1) कार्य का नाम उसके स्थान सहित:** पश्चिम रेलवे के भावनगर के (भूमिकार्य, ब्लेंकेटींग, साईड ड्रेन्स, रिटेईनींग वॉल, ट्रॉली रेफ्युजीस, छोटे/बडे पुलों, RUBs/LHS का निर्माण, संपूर्ण ट्रैक (बिछाने का और जोडने का) कार्य, ट्रैक का टेम्पींग, LWRs की तनावमुक्ति, P.way सामग्री का परिवहन, बलास्ट की आपूर्ति करने का और थोक में रखने का और अन्य सिविल इंजीनियरींग कार्य जैसे (संपूर्ण कार्य) समाविष्ट करते तमाम सिविल इंजीनियरींग कार्य,भीमनाथ अंतर्गत Y कनेक्शन सहित चैनेज- 1084.342 m सहित चैनेज :0.00 m (वर्तमान के ADI: 144.508 कि.मी.) भीमनाथ से चैनेज :21510.869 m तक धोलेरा लॉजिस्टीक हब तक नई लाईन का निर्माण। (दो पैकेट) **(2) कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 252,19,60,179.17/- **(3) जमा बयाना राशी:** ₹ 100,00,000.00/- **(4) निविदा प्रपत्र शुल्क:** निःशुल्क **(5) कार्य की समापन अवधि:** 24 (चौबीस) माह मॉनसुन सहित **(6) बीड जमा करने की तारीख एवं समय:** दिनांक: 17/08/2024 को 11:00 बजे। **(7) वेबसाईट विवरण नोटीस बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा का संपूर्ण विवरण देख सकते है एवं कार्यालय का पता:** वेबसाईट: www.ireps.gov.in उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II, पश्चिम रेलवे, द्वितीय तल, 'C' विंग, निर्माण भवन, डीआरएम कार्यालय के पास, असारवा, अहमदाबाद-382 345। CPM-029

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

२,५०० लोगों को किया रेस्क्यू; पूर्णा नदी दिखा रही रौद्र रूप

नवसारी, २७ जुलाई । दक्षिण गुजरात में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई जिलों में बारिश की वजह की कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ ने सबसे ज्यादा नवसारी जिले को प्रभावित किया है। पिछले २४ घंटे में नवसारी तालुका में १६० मिमी बारिश दर्ज की गई है इससे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है।

दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की वजह से इस समय कई गांव जलमग्न हैं। बाढ़ के कारण २,५०० से ज्यादा लोगों को उनके घरों से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि नवसारी जिले में गांवों और निचले इलाकों से कम से कम २,२०० लोगों को स्थानांतरित किया गया है, जबकि पड़ोसी तापी जिले में २४ घंटे में भारी बारिश के बाद ५०० लोगों को निकाला गया है।

नवसारी की डीएम क्षिप्रा अग्रे ने बाढ़ की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘नवसारी से होकर गुजरने वाली पूर्णा नदी २८ फुट पर बह रही है। यह खतरे के निशान २३ फुट से काफी ऊ पर है। जिले में बाढ़ ऊ परी बेसिन में पिछले २४ घंटे में हुई भारी बारिश के कारण आई है।’’ डीएम अग्रे ने बताया कि नवसारी शहर और आसपास के इलाकों में रहने वाले २,२०० लोगों को आश्रय गृहों में भेजा गया है, जहां १५ मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि जलभराव की वजह से ७० आंतरिक सड़कें और चार मुख्य सड़कें वाहनों के आने-जाने के लिए बंद कर दी गई हैं।

वहीं, तापी जिले के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने कहा कि बाढ़ के कारण वालोद तालुका के गांवों से ५०० लोगों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित किया गया है। वालोद, व्यारा, डोलवन और सोनगढ़ तालुका के गांवों में पानी भर गया है, जिससे ११३ आंतरिक सड़कें बंद हैं।

डोलवन तालुका में शुक्रवार सुबह ६ बजे तक पिछले २४ घंटे में १७३ मिमी बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, डांग जिले के सुबीर में १६४ मिमी, नवसारी तालुका में १६० मिमी, तापी के उच्छल में १४१ मिमी, सूरत के महुवा में १३३ मिमी, नवसारी के जलालपुर में १३० मिमी, नवसारी के गंडेवी में १२३ मिमी और तापी के वालोद में १०९ मिमी बारिश हुई।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य रखा है, उसकी प्राप्ति युवा पीढ़ी को ड्रग्स के अभिशाप से दूर रखकर ही संभव है: शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर यानि NCORD की 7वीं शीर्षस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अमित शाह ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य रखा है, उसकी प्राप्ति युवा पीढ़ी को ड्रग्स के अभिशाप से दूर रखकर ही संभव है।

हम सभी जानते हैं कि ड्रग्स का व्यापार और ड्रग्स का व्यसन भावी पीढ़ी को खोखला कर देती है। इसका आदी युवा अपने साथ-साथ अपने पूरे परिवार को भी घोर निराशा से ग्रसित कर देता है। आजादी के बाद दशकों तक देश पर राज करने वाली सरकारों ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में कोई कदम नहीं उठाया। बल्कि देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार में ड्रग्स का अवैध व्यापार लगातार फलता-फूलता रहा और परिणाम यह हुआ कि ड्रग्स का पूरा व्यापार नार्को टेरर के साथ जुड़ गया। आज ड्रग्स की कमाई से आने वाला पैसा देश की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बन गया है। लेकिन, साल 2019 में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने ड्रग्स के व्यापार को जड़ से खत्म करने के लिए इसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी। इसके साथ ही, एक नए सुबह का आगाज हुआ।

नशा मुक्त भारत के निर्माण में जुटे अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार, एजेंसियाँ और देश की 130 करोड़ जनता मिलकर ही नशे के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल कर सकती है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि जब तक देश का 35 वर्ष से कम उम्र का हर नागरिक इस लड़ाई को लड़ने और 35 वर्ष से अधिक आयु वाला हर नागरिक मार्गदर्शन का संकल्प नहीं करता तब तक नशे के खिलाफ लड़ाई को जीतना मुश्किल है।

इस मौके पर शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल `MANAS' की शुरुआत की। जिसके तहत एक टोल-फ्री नंबर 1933, एक वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप और उमंग ऐप होगा ताकि देश के नागरिक, नशीली दवाओं की तस्करी पर जानकारी साझा करने या नशीली दवाओं के दुरुपयोग, नशामुक्ति और पुनर्वास जैसे मुद्दों से संबंधित सलाह लेने के लिए चौबीसों घंटे 7 से जुड़ सकें।

वडोदरा के दशरथ गांव में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए छोड़ा गया सामान चोरी हो गया

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर फिलहाल वडोदरा शहर में काम चल रहा है. इस परियोजना का काम एलएंडटी कंपनी को सौंपा गया है और इसका उप-ठेका एक अन्य निजी कंपनी को दिया गया है। फिर इस कंपनी के लोगों ने माल को कंटेनर में बंद कर दिया. जिसमें से 25 हजार का माल तस्कर रात में चुरा ले गए। तो मैनेजर ने छानी थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई।

शानत के जगन्नाथ, मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और वर्तमान में थानी कैनाल रोड पर ग्रीनवुड फ्लैट्स में रहते हैं, एक आश्रय वाले किराए के घर में रहते हैं और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करते हैं। हमारी कंपनी एक जर्मन कंपनी से टाइप की गई है। हमारी कंपनी भारत में प्रमुख निर्माण अनुबंधों में काम करती है। वर्तमान में, भारत सरकार अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन पर काम कर रही है जिसमें वडोदरा से महमदाबाद तक का 90 किमी का सेक्शन सी-6 के नाम से जाना जाता है। बुलेट ट्रेन के काम का ठेका एलएंडटी कंपनी को दिया गया है. जिस कार्य के लिए एलएंडटी कंपनी ने हमारी कंपनी को उप-ठेका दिया है और एलएंडटी कंपनी का कार्यालय जो इंदिरा नगर दशरथ गांव में स्थित है। इसमें बुलेट ट्रेन का सामान बनाने के लिए बड़ी जगह है।

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122 , 9327086467 R.N.I. 63177/ 95